● वर्ष-3
● अंक-152
रायपुर, शनिवार
03 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› महिलाएं साबित होती हैं अच्छी...

असम के मुख्यमंत्री का दावा

राहुल के बॉडी डबल की हुई पहचान

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग जारी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक बार फिर हमला बोला है।

साथ ही दावा किया कि कांग्रेस की यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बॉडी डबल की पहचान कर ली है। बता दें हिमंत बिस्व सरमा ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि हमने राहुल गांधी के बॉडी डबल की पहचान कर ली है। हमने खुलासा किया है ज्यादातर रोड शो के दौरान राहुल गांधी भीड़ को उत्साहित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बॉडी डबल भीड़ का उत्साह बढ़ा रहा था। राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया और तस्वीर अपलोड की तो राहुल गांधी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में भाग लिए बिना चुपचाप असम से गुवाहाटी हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए निकल गए।

जो कांग्रेस की विचारधारा नहीं रखते उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए- राहुल

कांग्रेस से छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है, उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। जैसे असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा और मिलिंद देवड़ा ने किया। बता दें हिमंत बिस्व सरमा 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हिमंत बिस्व सरमा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। इस कारण उनकी सोच कांग्रेस विचारधारा से मेल नहीं खाती है। उन्होंने अपने सभा में कहा कि क्या आप हिमंत बिस्व सरमा की एक समुदाय पर की गई टिप्पणी को सुना है। हम ऐसी विचारधारा के कभी पक्षधर नहीं हैं।

व्यासजी तहखाने में मिली थी 10 मूर्तियां

8 को किया गया स्थापित, जलाई गई अखंड ज्योति

वाराणसी। काशी ज्ञानवापी मामले में जिस जगह पर पूजा पाठ चल रही है वहां पर मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया है। ट्रेजरी से व्यास तहखाने में 8 मूर्तियों को लाया गया है। सर्वे में व्यास तहखाने में 10 मूर्तियां मिली थी। शिव, गणेश, विष्णु, हनुमान की खंडित मूर्तियां हैं। आपको बता दें कि सर्वे में मिली 10 मूर्तियों में से फिलहाल 8 को वापस लाकर स्थापित किया गया है। जिसकी पूजा चल रही है। जिन मूर्तियों को स्थापित किया गया है वो सभी मूर्तियां खंडित हैं। जिनमें दो शिवलिंग और दो हनुमान जी की मूर्ति बताई जा रही है। एक खंडित मूर्ति भगवान विष्णु की है। एक लक्ष्मी जी की और एक गणेश जी की प्रतिमा है। राम लिखे जिस शिलापठ को एएसआई ने इस तहखाने से लिया था, उसका भी पूजन चल रहा है। सिर्फ मूर्तियों की ही पूजा नहीं बल्कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में 9 दिनों के रामायण का अखंड पाठ भी शुरू हो चुका है।

अखंड रामायण के पाठ के लिए चार-चार घंटे की पूजारी की शिफ्ट लगाई जाएगी। जिसमें 6 पूजारी लगातार 9 दिनों के इस अखंड रामायण के पाठ को कर रहे हैं। 1993 के पहले तीन बार इस तहखाने में रामायण का पाठ होता था। ऐसा हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया। ठीक वैसा ही कुछ अब फिर से देखने को मिल रहा है। मस्जिद समिति को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया.

रामलला की सुरक्षा के लिए इजरायल

इजरायल राम मंदिर के चारो तरफ अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला है। आपको तो बता ही है कि रामलला के दर्शन के लिए देश और दुनिया से हजारों-लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अयोध्या की सिक्योरिटी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस और इजरायल के बीच एक बड़ी डील हो गई है। हाल ही में कई कट्टरपंथी राम मंदिर के पास से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर के पास परिंदा भी पर नहीं मार पाए इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। इजराइल निर्मित एंटी-ड्रोन सिस्टम जल्द ही उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य शीर्ष महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा करने की संभावना है।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मंदिर के कोई सबूत नहीं, जमीयत चीफ मदनी बोले- कानून की किताब को आग लगा दो

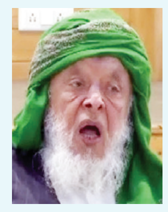

एक तरफ जहां ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत से पूजा की अनुमति मिलने के बाद वहां अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही सर्वे के दौरान मिली 10 मूर्तियों में से आठ मूर्तियों को स्थापित भी कर दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती भी दी जा रही है। वही अब पूरे विवाद पर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बयान सामने आया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जहां मस्जिद है, वहां मंदिर था इसका कोई सबूत नहीं है। मंदिर के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हां, अगर आप इसके आसपास जाएंगे तो वहां मंदिर ही मंदिर होंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर वहां मंदिर होता तो जिस तहखाना में मूर्ति लाकर रखी गई है और जिस मूर्ति पर रात में पूजा की गई है, यह मूर्ति नहीं लाई जाती बाहर से। यहां शुरू से ही कोई मूर्ति रही होगी। लेकिन यहां शुरू से ही कोई मूर्ति नहीं है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि यहां शुरू से ही मंदिर था और उसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई है?ज्ञानवापी मामले पर बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ऐसे फैसले से देश में आपसी दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि, कानून की किताबों को आग लगा दो। अगर यही चलता रहा तो किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को राहत देने से इनकार कर दिया. जिसने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17-18 को दिल्ली में

मिशन 400 पार में जुटी इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। इसे आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में चुनाव को लेकर महामंथन होगा। बैठक के लिए देशभर से हजारों नेताओं को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इससे बैठक के लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में अलग-अलग सत्र भी आयोजित किया जा सकते हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद, अलग-अलग राज्यों के विधायक और विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस महामंथन का हिस्सा बनेंगे। यह बैठक 17 फरवरी को शुरू होगी और 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जबकि नरेंद्र मोदी अधिवेशन बैठक के समापन सत्र को अपना संबोधन देंगे। उद्घाटन सत्र दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा। वही 18 तारीख को दोपहर 2:00 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। इसे दिल्ली के भारत मंडपम आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक से भाजपा आगामी चुनाव को लेकर अपना एजेंडा सेट करेगी। साथ ही चुनावी रणनीति भी तय की जाएगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा कई अन्य का भी संबोधन हो सकता है। इसके अलावा संगठन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी चर्चा हो सकती है और इसका जवाब कैसे देना है इस पर रणनीति बनाई जा सकती है। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 400 पर का लक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे मैं पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी।

यशस्वी जायसवाल का जलवा बरकरार, जड़ा टेस्ट करियर का दूसरा शतक (विस्तृत समाचार पेज-7 पर)

प्रमुख समाचार

भारत-मालदीव की दूसरी कोर ग्रुप की बैठक, भारतीय सैनिकों के मुद्दे पर चर्चा

नई दिल्ली। मालदीव में भारतीय सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर भारत और मालदीव के बीच दूसरे कोर ग्रुप की बैठक हुई। भारत-मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक दो सप्ताह से ज्यादा वक्त से दिल्ली में चल रही है। मालदीव के माले में हुई पहली बैठक में ठोस परिणाम नहीं निकला था। बता दें पिछले वर्ष के दिसंबर माह में दुबई में सीओपी28 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच एक बैठक के बाद दोनों पक्षों ने कोर ग्रुप स्थापित करने का निर्णय लिया था। गौरतलब है कि पिछले माह मालदीव के राष्ट्रपति मोइम्मद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को वापस जाने का 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। वर्तमान में लगभग 80 भारतीय सैनिक मुख्य रूप से दो हेलीकॉप्टर और एक विमान संचालित करने के लिए मालदीव में हैं, जिन्होंने सैकड़ों चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशनों को अंजाम दिया था। नवंबर में मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ तनाव आ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ने कहा कि वह भारतीय सैन्य कर्मियों को अपने देश से बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे को निभाएंगे।

सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज

आगरा। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरू रामभद्राचार्य महाराज को शुक्रवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधिकारी ने यह जानकारी दी। फिलहाल उन्हें वायुमार्ग से देहरादून ले जाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी को फोन करके उनका हालचाल जाना। जगद्गुरु की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। यहां दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश शर्मा ने बताया कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें यहां लाया गया, उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉ. नवनीत शर्मा उनका इलाज कर रहे हैं, कुछ जांच हो चुकी हैं जबकि कुछ जांचों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि शुरूआत जांच में छाती में संक्रमण की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, रामभद्राचार्य महाराज की चार साल पहले हृदय बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे में डॉक्टर हर तरह की जांच कर रहे हैं।

कैग रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यहां केंद्र सरकार से मिलने वाली बकाया धनराशि को लेकर दो दिवसीय धरना शुरू किया। इस दौरान ममता ने बजट से लेकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी केंद्र पर हमला बोला। कैग रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार राज्य का बकाया नहीं दे रही है। धरने के पहले दिन ममता ने कहा, उन्होंने कैग रिपोर्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कैग रिपोर्ट लेकर पहुंचीं ममता बनर्जी ममता ने कहा, कैग रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। इसे लकेर मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। कैग रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटें जीतेंगे। मैं दो सीटों की पेशकश कर रही थी, लेकिन वे और अधिक चाहते थे। मैंने कहा ठीक है, सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बंगाल में एक कार्यक्रम करने आई है.

मंत्री स्टालिन को बेंगलुरु की एसीएम कोर्ट ने किया तलब

बेंगलुरु। सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी के कारण तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब कर्नाटक के बेंगलुरु की 42वीं एसीएम कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। अदालत ने उदयनिधि से चार मार्च को पेश होने के कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों को भी समन जारी किया है। इससे पहले हाल ही में उन्होंने कहा था कि वे अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि उनकी टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं था। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। दरअसल, तमिलनाडु में संतानम उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इस सम्मेलन से जुड़ी एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उनको यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कुछ चीजें हैं जिनका हमें उन्मूलन (समाप्त) करना है और हम केवल विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये सभी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना है और सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातनम को खत्म करना और उसका विरोध न करना हमारा पहला काम होना चाहिए।

एक बार फिर भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सिखाया सबक

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से समुद्री लुटेरों का आतंक बढ़ गया है। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरे लगातार व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे है। पहले भी भारतीय नौसेना ने कई जहाजों को समुद्री लुटेरे से बचाया है। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और समुद्री डकैती के प्रयास को विफल कर दिया है। बता दें पाकिस्तानी और ईरानी चालक दल के सदस्यों वाला जहाज को समुद्री लुटेरों ने घेर लिया था। भारतीय नौसेना के कहा कि 31 जनवरी से मछली पकड़ने वाले जहाज पर समुद्री लुटेरों की पैनी नजर थी। गौरतलब है कि समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात आईएनएस शारदा ने खतरे को पहचान लिया था। आईएनएस शारदा ने शुक्रवार तड़के जहाज को रोका और चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए समुद्री लुटेरों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, इस दौरान नौसेना ने अपने हेलीकॉप्टर और रॉफ्ट का इस्तेमाल किया। जारी बयान में कहा गया कि इसमें 11 ईरानी और आठ पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। भारतीय नौसेना ने कहा कि समुद्री डकैती रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात मिशनों द्वारा प्रयास किए गए। भारतीय नौसेना ने 36 घंटों के भीतर दो बड़े बचाव अभियान चलाए और 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी नागरिकों सहित दो अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाजों और चालक दल के सदस्यों को बचाया।

देशभर में समान नागरिक संहिता लाने से क्यों बच रही मोदी सरकार

अमित शर्मा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर बनी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इस तरह समान नागरिक संहिता लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। असम, गुजरात और बाद में उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर यूसीसी लाने की चर्चा है। विपक्ष इसे मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश बता रहा है। उसके अनुसार यह हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की भाजपा की सोची समझी चाल है। लेकिन भाजपा के लिए समान नागरिक संहिता कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं रहा है। उसने हमेशा से अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया और समय आने पर इसे लागू करने की बात की है। यानी अब भाजपा मतदाताओं से यह कह सकती है कि उसने राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक के बाद समान नागरिक संहिता का एक और वादा भी निभा दिया है। सही मायने में कहें तो व्यावहारिक स्तर पर हिंदू समुदाय पर इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने पर बात की गई है। यह अभी 18 वर्ष हो सकती है। आने वाले समय में पुरुष और स्त्री सबके लिए विवाह की एक सामान उम्र करने की बात हो सकती है। ऐसा होने पर विवाह की उम्र सबके लिए न्यूनतम 21 वर्ष हो सकती है। यूसीसी के बाद सबके लिए तलाक लेने के लिए केवल अदालत जाना होगा। तीन तलाक, या तलाक की किसी भी प्रकार का तरीका अवैध हो जायेगा।

मुस्लिम समाज के कुछ विद्वानों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह उनके धर्म के मामलों में छेड़छाड़ है। यदि यूसीसी कानूनों के कारण उनकी धार्मिक परंपराओं में किसी भी तरह की बाधा आती है, तो वे इसे किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करेंगे। इससे तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि, कुछ मुस्लिम विद्वानों ने यह कहा है कि यूसीसी का कोई भी कानून इस्लाम की धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं है और इसे लागू करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, यह बात भी सही है कि पूरे देश में एक साथ लागू करने पर इस कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। संभवत: यही कारण है कि भाजपा ने इसे एक साथ पूरे देश में लाने की बजाय कुछ जगहों पर लाकर इसके असर का मूल्यांकन करना चाहती है। यदि बेहतर परिणाम मिले, तो बाद में इसे पूरे देश में लाया जा सकता है। फिलहाल, एक-दो राज्यों में लाकर भी भाजपा अपने मतदाताओं को वह संदेश देने में सफल रहेगी, जिस उद्देश्य से ठीक लोकसभा चुनावों के पहले इसे लाया जा रहा है।

बड़ा चुनावी पैंतरा

राजनीतिक विश्लेषक धीरेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा ने यूसीसी को हमेशा से अपने चुनावी एजेंडे में रखा और घोषणा पत्र में इसको जगह दी। ऐसे में आज उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने से भाजपा की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसे इसका बड़ा चुनावी लाभ मिल सकता है। विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल या केरल जैसे राज्यों में इसका बड़ा असर हो सकता है। बड़ा चुनावी वादा निभाने के कारण भाजपा को इसका बड़ा चुनावी लाभ मिल सकता है और उसकी सीटों की संख्या बढ़ाने में यह मुद्दा बड़ी भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा कि राजनीति की मूल परिभाषा में यह है कि राजनीतिक दल जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए नीतियां बनाएं और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इस दृष्टि से भाजपा ने वही काम किया है, जो इस देश का ज्यादातर मतदाता चाहता है। हिंदू ही नहीं मुसलमानों के बीच भी ऐसे लोग हैं जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। यूसीसी के माध्यम से लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाना जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बन सकें, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह देश और समाज को आगे बढ़ाने वाला कदम है।

इसी तरह यदि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं में तलाक का भय समाप्त हो सके, उन्हें भी किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार मिल सके तो इससे आज पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को भी इनकार नहीं है। यदि कुछ लोगों को कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है, तो उनसे इस पर बात कर सही रास्ता निकालना चाहिए।

बीईओ ऑफिस में गाली-गलौज और छात्राओं के साथ मारपीट के मामले में दोनों शिक्षक सस्पेंड

गौरेला पेंड्रा मरवाही। बीईओ ऑफिस में गाली-गलौज करने वाले प्रधान पाठक और छात्राओं के साथ अभद्रता करने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीईओ कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों एवं कर्मचारी से गाली-गलौज कर मारपीट की धमकी देने और शासकीय काम में बाधा पहुंचाने वाले प्रधान पाठक होशेलाल टंडन एवं छात्राओं से मारपीट करने और छात्राओं को स्कूल से घर तक उनका पीछा करने के मामले में शिक्षक मयंक शर्मा को बिलासपुर के संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों शिक्षकों के विरुद्ध मिले शिकायत की जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक ने यह कार्रवाई की है।

पहला मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हरिपुर विकासखंड गौरेला में पदस्थ प्रधान पाठक होशेलाल टंडन के द्वारा 29 दिसम्बर को बीईओ कार्यालय गौरेला में जाकर अधिकारी एवं कर्मचारी से गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायत गौरेला के बीईओ डॉ. संजीव शुक्ला ने जीपीएम जिले की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया से की। इसके बाद कलेक्टर द्वारा इस मामले की जांच कराई गई थी और होशे लाल टंडन को कारण बताओं नोटिस जारी कर उसे जवाब भी मांगा गया था। परंतु समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त मामले में जांच के बाद कार्यालय कलेक्टर जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पत्र 24 जनवरी 24 द्वारा होशे लाल टंडन प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला हरिपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई थी। जिसके आधार पर बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने बुधवार को होशे लाल टंडन को सस्पेंड कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न कर दिया है।

इसी तरह दूसरा मामला पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सारबहरा में पदस्थ शिक्षक मयंक शर्मा के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी जेके शास्त्री को शिकायत मिली थी कि शिक्षक मयंक शर्मा के द्वारा आवंटित किया गया अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है तथा छात्राओं के साथ मारपीट की जाती है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि मयंक शर्मा विलंब से स्कूल आते हैं और प्रधान पाठक के निर्देशों का पालन नहीं करते बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। साथ ही शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भी मयंक शर्मा पर आरोप लगाया गया था कि शर्मा छात्राओं से गलत हरकत करते हैं एवं उनका पीछा घर तक करते हैं। उपरोक्त शिकायत की जांच के बाद डीईओ जेके शास्त्री के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक मयंक शर्मा को संयुक्त संचालक के द्वारा सस्पेंड कर उन्हें बीईओ कार्यालय गौरेला में अटैच कर दिया गया है। उपरोक्त दोनों शिक्षकों को सस्पेंड अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

क्रास फायरिंग से हुई मौत संदेहास्पद, सर्व आदिवासी समाज ने जांच की मांग की

बीजापुर। जिले में नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मासूम बच्चे सहित आम ग्रामीण की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि ऐसी घटनाओं से आम लोगों के बीच अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। उन्होने ऐसी मौत पर संदेह जताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है।

सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों ने बयान जारी कर कहा है कि बीते जनवरी माह में मुदवेंदी में 6 माह की मासूम की गोली लगने तथा बोडग़ा गांव के युवक रमेश ओयाम की कथित नक्सल मुठभेड़ में क्रास फायरिंग में गोली लगने से मौत होना बताया जा रहा है। इन घटनाओं को लेकर आदिवासी समाज को संदेह हो रहा है। समाज का मानना है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों मुठभेड़ के दौरान आदिवासियों को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अवैधानिक है। आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के नैसर्गिक रक्षक हैं तथा यहां स्वच्छंद रूप से रहना चाहते हैं। लगातार क्रास फायरिंग में आम लोगों की मौत चिंताजनक और संदेहास्पद है।

उन्होने कहा कि 30 जनवरी को कथित मुठभेड़ के बाद क्रास फायरिंग से हुए रमेश ओयाम की मौत के बाद शव को भैरमगढ़ लाने वाले ग्रामीणों को पुलिस द्वारा आखिर क्यों रोका गया था। सर्व आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि मण्डल को ग्रामीणों और पुलिस के आला अधिकारियों से वार्ता कर शव को पीएम कार्रवाई तथा मृत्यु की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आना पड़ा था। सर्व आदिवासी समाज शासन प्रशासन से मांग करता है कि इन घटनाओं की न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। अन्यथा आदिवासी समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी।

धरनास्थल पर दूसरे दिन भी डटे रहे वन कर्मचारी

कहा- मांगें पूरी नहीं होंगी तो काम नहीं होगा

कोरबा। रिक्त पदों के खिलाफ संविदा नियुक्ति का विरोध कर रहे वन कर्मचारियों ने कोरबा जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी कुल चार मांगें हैं, जिसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसे पूरा किया जाए। कोसाबाड़ी स्थित वन परिसर में कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के पहले दिन मांगों के बारे में बातचीत की और सरकार तक यह संदेश भिजवाया कि इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार किया जाए।

छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रीतम पुरैन ने बताया कि चार मांगे हैं। उन्होंने कहा, %फील्ड पर 24 घंटे हम उपस्थित रहते हैं। अन्य विभाग के हमारे समक्ष कर्मचारी आठ घंटे ड्यूटी करके अपने बाकी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हम सभी कर्मचारी 24 घंटे अपने कर्तव्यों के शासकीय कर्तव्यों में बने रहते हैं फिर भी हमारा वेतन अन्य विभाग के समक्ष कर्मचारियों से कम है। इसका हम पूरा-पूरा विरोध करते हैं।

वनरक्षक उषा कुमारी ने कहा, %चार सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारी चार सूत्रीय मांग बहुत महत्वपूर्ण हैं। 180 पद संविदा में भर्ती लिया गया है उसको बंद किया जाए और हमारी प्रमोशन बाधित हो रही है। हमारी ग्रेड पे जो वर्क को 2800 रुपये और उपवन क्षेत्र को 4200 पर होना चाहिए एवं हमारी तीसरी मांग है जो बहुत वर्षों से सेटअप नहीं किया गया है सेट अपपुनरीक्षण किया जाए।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सफलतापूर्वक चलाया जा है मेरी सहेली अभियान

- **मेरी सहेली की टीम की 13 मुख्य स्टेशनों पर मौजूद**

बिलासपुर। देश की धड़कन भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग रेल से सफर करते हैं। रेलयात्रियों को सुरक्षित एवं संरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना रेल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रेनों में अकेली यात्रा कर रही महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चला रही है। मेरी सहेली अभियान रेलवे की एक महिला-उन्मुख पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी यात्रा को आरामदायक और निर्बाध बनाना है।

कामकाजी व घरेलू महिलाओं के साथ ही पढ़ाई के लिए लड़कियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना-जाना लगा रहता है। लंबे सफर के दौरान कई महिलाओं को घबराहट होती है तो उनके परिजन उनसे ज्यादा चिंता में पड़े रहते हैं। जब तक सफर सकुशल पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी चिंता का समाधान नहीं होता। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली अभियान चलाया है। इस सक्रिय पहल का मूल उद्देश्य महिला यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा की गहरी भावना प्रदान करना है, जिससे वे अपनी सुरक्षा के बारे में किसी भी आशंका के बिना यात्रा कर सकें। जिसके तहत विभिन्न स्टेशनों पर मेरी सहेली टीमों का गठन किया गया है। यह टीम महिलाओं को विभिन्न अपराध से लेकर मदद लेने के लिए हेल्पलाइन के बारे में जागरूक भी करती रहती हैं। इसके अलावा किसी भी परेशानी के दौरान अगर महिलाएं 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती हैं तो उन्हें तुरंत रिस्पॉंस दिया जाता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मेरी सहेली की 13 टीम कार्यरत है, जो कि 13 अलग-अलग ट्रेनों को कवर करती है। रेलवे सुरक्षा बल की मेरी सहेली टीम में महिला कांस्टेबल से लेकर महिला सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर शामिल है। रेलवे सुरक्षा बल सिस्टम के माध्यम से मेरी सहेली टीम को संबन्धित स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रा कर रही अकेली महिला यात्रियों की जानकारी प्राप्त होती है। अकेली यात्रा कर रही महिला यात्री की जानकारी मिलने के पश्चात मेरी सहेली टीम उनसे जाकर संपर्क करती है, उनसे बातचीत कर उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या की जानकारी लेती है और सफर के दौरान संबंधित कोचों और बर्थों की निगरानी करती है। सफर के दौरान महिला यात्री हेल्पलाइन 139 एवं टीटीई के माध्यम से भी मेरी सहेली टीम से संपर्क कर सकती है।

नक्सलियों ने पुलिया निर्माण में लगे वाहनों को किया आग के हवाले

नक्सलियों ने फिर दिखाया विकास विरोधी चेहरा

नारायणपुर। नक्सलियों ने एक बार फिर आदिवासी विकास विरोधी चेहरा सामने आया है। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जीवलापदर में पुल के निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। आगजनी की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, आदिवासियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए जीवलापदर के समीप नाले में पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण की जानकारी मिलने पर करीबन 50 की संख्या में हथियारबंद नक्सली मौके पर पहुंचे और पुलिया निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यहां तक पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मोटर साइकिल को अपने साथ ले गए। पूरा मामला नारायणपुर के कुरूषनार थाना क्षेत्र का है।

जानकार बताते हैं कि अबूझमाड़ के दुरुस्थ इलाकों से इस तरह की वाहनों को आग लगाने, सड़क खोदने, सड़क पर पेड़ गिराने जैसी खबरें बीच-बीच में आती रहती हैं। इस तरह की खबरें जानबूझकर नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों के जरिए फैलाई जाती है, जिससे फोर्स जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे। फोर्स के पहुंचने पर पहले से एम्बुश लगाए बैठे नक्सली हमला कर देते हैं।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा 5 मार्च से

जगदलपुर। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 5 मार्च से शुरू होकर 24 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस बार परीक्षा में 53 हजार 385 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के आयोजन के संबंध में विवि के अकादमिक भवन में संबद्ध कॉलेजों के प्राचायों की बैठक हुई। कुलसचिव अभिषेक कुमार बाजपेयी ने इस दौरान परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार समय सारिणी जारी की गई है। स्नातक कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थी 15708, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी 35547, भूतपूर्व परीक्षार्थी 260 एवं पूरक परीक्षार्थी 1870 यानी कुल 53385 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षाएं तीन पालियों में क्रमश: प्रथम पाली सुबह 7 से 10 बजे तक, द्वितीय पाली सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक और तृतीय पाली में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी।

जिला अधिवक्ता संघ कोंडागांव के अध्यक्ष बने दीपक ठाकुर

कोंडागांव। जिला अधिवक्ता संघ कोंडागांव के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि कुल मतदात 64 में से 62 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया जिसमें दो डाकमत पत्र प्राप्त हुए। मतगणना उपरांत अध्यक्ष पद पर दीपक ठाकुर एवं उपाध्यक्ष पद पर असलम खान को विजयी घोषित किये गये। अन्य पदाधिकारीगण में सचिव पद प्रशांत दत्ता, सह सचिव गौरव जैन, कोषाध्यक्ष मदन हलदार, सांस्कृतिक सचिव जयदेव साहू, क्रिडा सचिव नितेश जैन एवं कार्यकारणी सदस्य महेन्द्र कौशल, गोपाल दीक्षित, नरेश कुमार नाईक एवं कंवल सिंह बघेल को निर्विरोध चुना गया। अधिवक्ता दीपक ठाकुर के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर लखन पटेल, प्रशांत ठाकुर, सुरेंद्र भट्ट, कन्हैया देवांगन, सारंग धर कोशिक, प्रशांत मिश्रा, धन्नू साहू, गोपाल दीक्षित, वलय राहा, तिलक पांडे, महेश बघेल, दुर्गेश जोशी, अनिष श्रीवास्तव, दिनेश ध्रुव, सगा राम कोर्राम, प्रशांत दत्ता, गौरव जैन, रति राम, उमा मानिकपूरी, जयदेव साहू, राम लाल, निशांत दत्ता आदि ने बधाई दी है।

बैगा जनजाति के मौत मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

कबीरधाम। कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत माठपुर के आश्रित गांव नागाडबरा में झोपड़ी में 15 जनवरी को आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। जिन तीन लोगों की मौत हुई है, वे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के हैं। इस मामले को लेकर परिजन हत्या का संदेह जता रहे हैं। वहीं, कांग्रेस भी इस मामले में शुक्रवार को कुकदूर में धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता नीलू चंद्रवंशी के नेतृत्व में पीड़िता बैगा परिवार व कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। नीलू चंद्रवंशी ने बताया कि यह घटना पूरी तरह से संदेहास्पद है। घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास दीवार में खून के छींटे हैं। घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस गांव में बुधराम (35) पुत्र भोपसिंह, हिरमतीन बाई (32) पत्नी बुधराम और उनके 12 वर्ष के बेटे जोन्हू की मौत हुई है। पुलिस का दावा है डॉक्टर ने मृतका हिरमती बाई (32), जोन्हू (12) के शव जल जाने से मौत का कारण न बता पाना लिखा है।

सेवानिवृत्त हो रहे 16 कर्मचारियों को दिया पेंशन प्राधिकार पत्र

जगदलपुर। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने कहा कि लम्बी अवधि तक शासकीय सेवा देने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को शासकीय नियमों के अनुसार उनके हक एवं पात्रता अनुसार सभी स्वत्वों का समय पर भुगतान करने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के प्रकरणों पर संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों की स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। कलेक्टर ने शुक्रवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में माह जनवरी में सेवानिवृत्त हुए 16 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पुष्पमाला एवं शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किए। वहीं इन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पीपीओ पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री संजय सोनवानी ने बताया कि इस माह सेवानिवृत्त हो रहे 16 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र जारी की गई है।

फरार स्थाई वारंटी एक नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। जिला में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना भोपालपटनम् एवं केरिपु 170/बी चेरपल्ली की संयुक्त टीम ग्राम करकावाया की ओर निकली थी। अभियान के दौरान ग्राम करकावाया से नक्सली वारदात के बाद से फरार नक्सली महेश तलाण्डी पिता इस्तारी उम्र 38 वर्ष निवासी करकावाया थाना भोपालपटनम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महेश तलाण्डी के विरूद्ध थाना भोपालपटनम में 3 स्थाई वारंट भी लंबित है। गिरफ्तार नक्सली आरोपी के विरूद्ध थाना भोपालपटपनम् में वैधानिक कार्यवाही उपरान्त न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नक्सली थाना भोपालपटनम् क्षेत्रान्तर्गत 1 नवंबर 2009 को कुचनूर के जंगल में हुए मुठभेड़ में शामिल था, 19 मार्च 2009 को पोषणपल्ली मंदिर के पास पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की वारदात में शामिल था एवं 15 अप्रेल 2009 को चुनाव सुरक्षा डयूटी में तैनात बल को पोषणपल्ली के पास फायरिंग करने की वारदात में शामिल था।

हथिनी को करंट से मारकर कई टुकड़ों में बांटा

- **12 गड्ढों में किया दफन, अब तक 10 आरोपी जेल में**

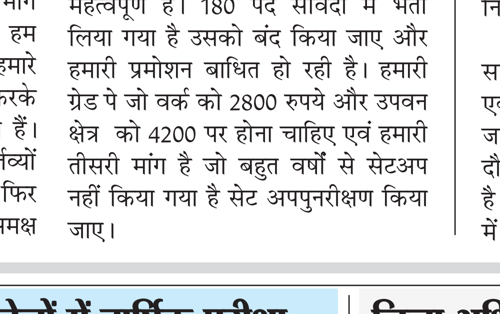

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के रमकोला एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर से लगे घुई के धुरिया जंगल में करंट की चपेट में आकर हथिनी की मौत हुई थी। आरोपियों ने शव के कई टुकड़े कर 12 गड्ढों में अलग-अलग दफनाया था। उक्त मामले में वन विभाग ने 7 और ग्रामीणों को आरोपी बनाया है। गुरुवार को कोर्ट में पेशकर वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वही इस मामले में तीनों आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।

मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र घुई अंतर्गत धुरिया के जंगल से लगे खेतों में ग्रामीणों के द्वारा फसल लगाई गई थी। फसल को जंगली जानवरों ने सुरक्षा के लिए जीआई तार फैलाकर करंट लगाया था। इसकी चपेट में आने से हथिनी की मौत हो गई थी।

ग्रामीणों ने बेरहमी से हाथियों के शव के कई टुकड़े कर अलग-अलग 12 गड्ढों में शरीर के विभिन्न हिस्सों को दफन किया था। इसकी सूचना बीते रविवार को डीएफओ पंकज कमल को मिली थी। इसमें वन अमले ने गड्ढों में दफन हथिनी के अवशेषों को बरामद किया था। मामलों में आरोपित रामचंद्र 31 वर्ष, माधव सिंह 27 वर्ष, प्राणबोधी 34 वर्ष, बैजनाथ 54 वर्ष, लालमोहन 48 वर्ष, गंगाराम 28 वर्ष व रामकृष्ण 29 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

मामले की जांच के बाद 29 जनवरी को वन अमले ने तीन आरोपी नरेंद्र सिंह 35 वर्षीय, जनकुराम 50 वर्षीय व रामचंद्र अगरिया 30 वर्ष को गिरफ्तार किया था। जिसमे प्रतापपुर न्यायालय से जेल भेज दिया गया था। एक आरोपी फरार बताया जा रहा था। इसी बीच घटना में सिर्फ चार लोगों की खबर पर मामले की विस्तृत जाँच की गई। तो इसमें 10 लोगों की संलिप्त होने का खुलासा हुआ।

सूरजपुर बलरामपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए अक्सर जंगलों के भीतर करंट के फंदे का इस्तेमाल किया जाता है। जिनकी चपेट में आने से अब तक कई हाथियों के मौत हो चुकी है। कुछ ग्रामीण भी इस फंदे की चपेट में आने से अपनी जान गवा बैठे हैं और कई हाथियों के मरने के मामले में सलाखों में बंद है। उसके बावजूद हाथियों को करने का सिलसिला नहीं रख रहा है।

वनों से लगाव है तो पेड़ों की कटाई पर लगाएं रोक: जावेद

- **हसदेव जंगल को लेकर किरण देव पर साधा निशाना**

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बस्तर संभागीय प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने जगदलपुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक को वनों से इतना ही लगाव है तो हसदेव में काटे जा रहे वनों की कटाई पर रोक लगाएं, जिससे जंगल को बचाया जा सके।

पिछले दिनों विधायक किरण देव ने वन संरक्षक एवं वनोपज आधारित आजीविका संवर्धन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में वनों का विशेष महत्व है। हमें वनों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन आज कोल माइनिंग के नाम पर छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के ही संरक्षण में हसदेव के लाखों वनों को काटा जा रहा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुकदर्शक बने बैठे हैं।

एक तरफ हसदेव वनों की रक्षा करने के लिए आगे आने वालों को नजरबंद कर वनों की कटाई की जा रही है। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वनों की रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित कर क्या खुद की सरकार के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से मोर्चा खोल रहे हैं। जबकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। वे खुद आज छत्तीसगढ़ भाजपा के नेतृत्व कर्ता हैं। जावेद ने कहा है कि यदि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जगदलपुर विधायक किरण देव की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और वे सच में प्रकृति प्रेमी हैं तो उन्हें तत्काल प्रदेश की जनता की जनभावनाओं, आदिवासियों के जल-जंगल और जमीन के हित को ध्यान में रखें। आदिवासियों के हसदेव वनों के लिए लगातार किये जा रहे संघर्ष को देखते हुए हसदेव के वनों की कटाई पर रोक लगवाने की पहल करनी चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

सरोज पांडेय के दायर याचिका पर गवाह की वास्तविकता की होगी जांच

बिलासपुर। भाजपा नेता सरोज पांडेय के खिलाफ के खिलाफ लेखराम साहू ने चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को विन्सेंट डिसूजा और अमोल मानस्वरे का प्रति परीक्षण किया जाएगा। कल इस मामले में लेखराम की गवाही और प्रति परीक्षण पूरा हो गया। बता दें कि वर्ष 2018 के राज्यसभा चुनाव में लेखराम साहू ने भाजपा नेता सरोज पांडेय के खिलाफ राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के पहले यह आपत्ति की गई थी कि पांडेय के कई समर्थक और प्रस्तावक जो कि चुनाव में मतदाता भी हैं, लाभ के पद पर होने के कारण अनुपयुक्त हैं। लिहाजा वे चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। इस आधार पर साहू ने पांडेय के नामांकन को रद्द करने की मांग की थी। चुनाव के बाद साहू द्वारा लगाई गई चुनावी याचिका में उपरोक्त बातों के अलावा इस बात को आधार बनाया गया था कि सरोज पांडेय ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी हैं और कुछ तथ्यों को छुपाया है। मामले में जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में प्रति परीक्षण हुआ है। इसमें सरोज पांडेय की ओर से एडवोकेट अभिषेक वैष्णव और लेखराम साहू की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा उपस्थित हुए।

कांग्रेस की बैठक से गायब रहे 88 पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस

रायपुर। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। जिसमें 1 फरवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें ज्यादातर पदाधिकारी गायब थे। प्रदेश प्रभारी की बैठक से नदारद रहे। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अल्पसंख्यक विभाग) के अध्यक्ष अमीन मेमन ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ सभी से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक बिना कोई सूचना दिए 88 पदाधिकारी बैठक से नदारद थे। इसमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 51 प्रदेश सचिव और 9 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। बता दें कि ये बैठक राजीव भवन में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब ने बुलाई थी। जिससे कई पदाधिकारी गायब थे।

राजेश मिश्रा को मिली संविदा नियुक्ति, आदेश जारी

रायपुर। आईपीएस अफसर राजेश मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति दी है। फिलहाल उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गयी है, वो अभी ओएसडी पुलिस मुख्यालय होंगे। राज्य सरकार ने उन्हें 1 साल के लिए संविदा नियुक्ति दी है। 1990 बैच के आईपीएस राजेश मिश्रा लंबे समय से केंद्र में रहे। हालांकि उनका नाम डीजीपी के लिए भी चल रहा था, लेकिन उन्हे एक्सटेंशन नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो 31 जनवरी को रिटायर हो गये। राजेश मिश्रा को अब राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति दी है।

मदरसा बोर्ड का छात्र संपर्क कार्यक्रम 6 से

रायपुर। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु दस दिवसीय छात्र संपर्क कार्यक्रम का आयोजन 6 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। रायपुर जिले के परीक्षार्थियों हेतु उर्दू कन्या हा. से. स्कूल, शास्त्री बाजार रायपुर को छात्र संपर्क केन्द्र बनाया गया है। 6 फरवरी से 11 बजे से कक्षाऐं प्रारंभ होंगी। दस दिवसीय छात्र संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कक्षाओं में विषयवार शिक्षक- शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन कराया जायेगा।

छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों बढ़ेगा तापमान, ठंड से मिलेगी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। आगामी दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री का अंतर रहा। इससे ठंड में कमी आई है। वहीं प्रदेश में सबसे ठंड इलाका बलरामपुर रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले दिन की द्रोणिका पश्चिमी विदर्भ से मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आगामी दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 7 हजार करोड़ की सौगात

सीएम साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा- यही तो है डबल इंजन की सरकार, फर्क साफ है

रायपुर। मोदी सरकार ने गुरुवार को नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे अब मोदी सरकार में 7 हजार करोड़ मिले हैं। यही तो डबल इंजन की सरकार है।

सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, छत्तीसगढ़- 2014 से पहले और 2014 के बाद 2009 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब रेलवे विकास के लिए ?311 करोड़ मिलते थे। आज पीएम मोदी की सरकार है। रेलवे विकास के लिए लगभग ?7000 करोड़ मिले हैं। यही तो डबल इंजन की सरकार है। फर्क़ साफ़ है।

बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। ये राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे। जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है।

सीएम साय ने धान खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुसौर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर धान का तौल भी करवाए। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से चर्चा की और धान बेचने में होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा।

पुसौर धान खरीदी केंद्र धान बेचने आए किसानों से सीएम विष्णुदेव साय ने चर्चा की। उन्होंने किसानों से पूछा कि धान बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा अंतर की राशि जल्द किसानों को मिलेगी। सीएम साय ने अपने सामने धान का तौल करवाया और मॉइश्चर मीटर से नमी भी मपवायी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को किसानों ने मुख्यमंत्री साय का संवेदनशील निर्णय बताया और धान बोनस भुगतान के लिए भी आभार जताया। सीएम साय ने किसान हित में छुट्टी के दिनों में भी खरीदी करने की घोषणा की है।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा : कांग्रेस नेताओं ने रूट का लिया जायजा

बलरामपुर/रामानुजगंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पहुंचने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर शुक्रवार को यात्रा के प्रभारी सुशांत मिश्रा, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समते कई कांग्रेस नेता प्रस्तावित रूट का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्रवेश करते ही प्रस्तावित रूट का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की।

पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर दूरी से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। संभावित रूप से फरवरी माह में बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रवेश करेगी, जिसे लेकर हम सब रूट का जायजा लेने एवं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्तोओं से चर्चा करने आए हैं। उन्होंने बताया कि बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की यह यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी।

जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा संभाग में पहुंचने को लेकर संभाग के लोगों में भारी उत्साह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी अहमद

ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकल जा रही है जिससे पूरे भारत के लोग जुड़ रहे हैं। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरगुजा राकेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सफी अहमद बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रस्तावित रूट पर दर्जनों जगह रुककर स्थानीय लोगों को यात्रा के विषय में जानकारी दी। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को यात्रा के दौरान सम्मिलित रहने की अपील भी। यात्रा के प्रभारी एवं पूर्व संसदीय सचिव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रस्तावित रूट के निरीक्षण बाद झारखंड के ग्राम गोदरमाना भी पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी गढ़वा जिले के अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी एवं अन्य स्थानीय कांग्रेस नेताओं से चर्चा कर उनके संभावित जनसभा के लिए कभी विस्तृत चर्चा की।

अपना पद और पार्टी छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा

भाजपा नेता को मिला धमकी भरा पत्र, प्रशासन से की सुरक्षा की मांग

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, दरभा मंडल के प्रभारी और जगदलपुर नगर निगम में पार्षद योगेंद्र पांडेय को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। जिसमें नक्सलियों ने लिखा कि बार-बार समझा रहे हैं, लगता है समझ नहीं आ रहा है, अपना पद और पार्टी छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सीधे जान से हाथ धो बैठोगे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसे आखिरी चेतावनी समझना। यह पत्र पोस्ट के माध्यम से उनके घर पहुंचा है। पत्र मिलने के बाद योगेंद्र पांडेय ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भी दिया है क्योंकि पूरे परिवार में डर का माहौल है।

पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में योगेंद्र पांडेय ने लिखा है कि राजवाड़ा सुभाष वार्ड क्र-09 जगदलपुर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर के उपाध्यक्ष पद पर पदस्थ होने के साथ ही रमैया वार्ड -17 का निर्वाचित वार्ड का पार्षद हूं, इससे पहले निगम अध्यक्ष के दायित्व में सेवा देने के साथ ही पार्टी के आदेश के अनुसार दरभा मण्डल का प्रभारी का भी दायित्व संभालने की बात कही है। इसके पहले भी एक बार फोन के द्वारा धमकी दी जा चुकी है, और

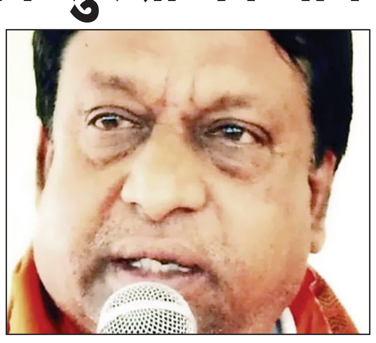

पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, जिसकी सुचना पुलिस प्रशासन को पहले भी दी है।

एक फरवरी को पुन~ पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला। पोस्ट के माध्यम से जिसमें पार्टी पद को छोडने एवं जान से मारने की धमकी लिखी हुई है, मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही समय रहते हुए किया जाना उचित होगी क्योंकि मुझे भी ऐसा प्रतित हो रहा है कि मुझे जान का खतरा है, इसके पहले 2003 से लेकर 2018 तक मेरे सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई थी। लेकिन अचानक 2018 में वापस ले ली गई वो भी बिना सूचना के, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान किया जाए।

छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश के 50 न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल

- **मुख्य न्यायमूर्ति बोले- न्यायधीशों को अच्छे प्रबंधन और कौशल विकसित करने के साथ तकनीकी रूप से निपुण होना चाहिए**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में बांग्लादेश के 50 न्यायिक अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में मुख्य न्यायाधिपति रमेस सिन्हा ने अकादमी पहुंचकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को यादगार बना दिया। मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने न्यायपालिका में न्यायालय प्रबंधन और तकनीक के उपयोग विषय पर सारगर्भित व्याख्यान देते हुए कहा कि, न्यायपालिका का मुख्य कार्य निष्पक्ष और शीघ्र न्याय प्रदान करना है।

उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात पर जोर दिया कि, न्यायधीशों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए न केवल अच्छा प्रबंधक होना आवश्यक है बल्कि तकनीकी रूप से निपुण होना भी आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्य और न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग प्रक्रिया से भी बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायधीशों की व्यवसायिक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बारीकी से तैयार किया गया था। इस

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवक्ता के रूप में कानून के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायायल के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ। निर्मल शुक्ला, फौज़िया मिर्ज़ा ने बांग्लादेश से आए न्यायाधीशों के समक्ष व्याख्यान दिया। बांग्लादेश से आए न्यायधीशों को अधिवक्ता अमृतो दास और नौशीना अली ने संबोधित किया था। हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय के विधि संकाय से अनिन्द्य तिवारी और कलिंगा विश्वविद्यालय के आयुष गोंडाले ने भी न्यायधीशों को विभिन्न विषयों पर संबोधित किया। प्रशिक्षण का एक-एक सत्र वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी अरूण पाण्डेय, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल अशोक पण्डा और राज्य के न्यायिक अधिकारी श्री के.एल। चरयाणी और पंकज शर्मा ने भी लिया। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की निदेशक सुषमा सावंत और अतिरिक्त निदेशक गरिमा शर्मा ने भी भारत में प्रचलित विधिक सिद्धांतों से बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराया।

इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के हॉस्टल में की गई थी। यह सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी के पेट्रन-इन-चीफ और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के चेयरमैन, न्यायाधिपति संजय के। अग्रवाल ने न केवल प्रशिक्षण की प्रत्येक व्यवस्थाओं पर अपनी नजर रखी बल्कि प्रत्येक कदम पर अकादमी के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने लगातार दो दिन एक-एक सत्र में दांडिक अपील और सिविल अपील के संबंध में विस्तारपूर्वक न्यायिक अधिकारियों को संबोधित किया। बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को उनके दोनों ही सत्र उपयोगी लगे। अकादमी के अन्य सदस्य न्यायाधिपति राकेश मोहन पाण्डेय ने भी जमानत के प्रावधान विषय पर व्याख्यान दिया और इस व्याख्यान सत्र में उन्होनें जमानत से संबंधित विभिन्न प्रावधानों एवं न्याय दृष्टांतों से अधिकारियों को अवगत कराया। यह प्रशिक्षण इस मायने में एक ऐतिहासिक महत्व के रूप में दर्ज हुआ कि पहली बार राज्य न्यायिक अकादमी ने देश की सीमा के बाहर के न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

रायपुर, दुर्ग-भिलाई समेत 45 ठिकानों पर आईटी का छापा

जब्त किए नगदी रकम और जेवर, कार्रवाई जारी

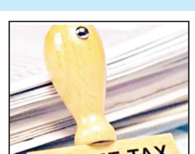

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे इलाकों में आईटी विभाग की कार्रवाई जारी है। चर्चा है कि कलेक्टर और महत्वपूर्ण पदों पर रहा चुके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर के घर दफ्तर पर भी केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा है। ऐसे आईटी विभाग लगभग 45 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही प्रदेश के बड़े कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। चर्चा है कि इस दौरान आईटी की टीम ने करोड़ों रुपये नगदी, सोने-चांदी के जेवरात और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। आयकर विभाग के सीनियर अफसर भोपाल से रायपुर पहुंचे हुए हैं, जो कि दस्तावेज खंगाल रहे हैं। बीते दिनों बुधवार से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई जारी है।

अलग-अलग जगहों पर एक साथ पड़ा छापा

आयकर विभाग की टीम राजधानी रायपुर समेत अंबिकापुर और दुर्ग-भिलाई के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी। रायपुर के राजीव नगर स्थित चंद्रभान शेरवानी और कारोबारी अमर होरा के घर पर छापेमारी की है। तेलीबांधा में संदीप जैन के ठिकानों पर दुर्ग-भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में आईटी की टीम ने छापेमारी जारी है। रामनगर स्थित बिल्डर अजय चौहान के ऑफिस और मौर्या टॉकीज स्थित चौहान इस्टेट में और दुर्ग ग्रीन चौक स्थित हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर भी आईटी की टीम की जांच जारी है। वहीं भिलाई में भी आईटी टीम की कार्रवाई जारी है।

घर पर चल रहा इनकम टैक्स का छापा, छत पर योगा में मशगूल पूर्व मंत्री भगत

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। लेकिन पूर्व मंत्री आईटी की कार्रवाई से बेफिकर घर के छत पर योगासन करते हुए नजर आए। जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा कारोबारी चौहान बिल्डर्स, प्रदीप जैन, विजय जैन, संदीप जैन, पप्पू बंसल, चंद्रभान शेरवानी समेत 47 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन छापेमारी कार्रवाई में आयकर विभाग के सीनियर ऑफिसर भोपाल से रायपुर पहुंचे हुए हैं। बलरामपुर के राजपुर में पूर्व खाद्यमंत्री के निज सहायक समेत रायपुर के एमएलए कॉलोनी स्थित पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर कार्रवाई जारी है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 29.01.2024

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र 'अ' में प्रतिशत दर पर दिनांक 13.02.2024 तक आमंत्रित की जाती है:-

निविदा आमंत्रण स.क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	आमंत्रण
346/दुर्ग(कवर्धा)/2023	प्रतापपुर भगतपुर निंगापुर मार्ग लं. 1 से 4 = 4.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	63.45	चतुर्थ

टीप- 1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.egstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. कमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें ।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग
दूरभाष - 0788-2210876

जी-07430/7

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-2, सिरपुर भवन परिसर रायपुर (छ.ग.)

(निविदा आमंत्रण सूचना)

कमांक-564/NIT-29/2023-24/नि.लि. दिनांक 31/01/2024

1. निविदा प्रपत्र जमा करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- 12.02.2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
2. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 19.02.2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि :- 20.02.2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
5. निविदा प्रपत्र की कीमत प्रत्येक हेतु (रू. में) :- रूपये 750.00
6. निविदा प्रपत्र का प्रकार :- प्रपत्र 'A'
7. निविदाकारों की श्रेणी :- द-पंजीयन के अंतर्गत 'द' से 'अ' श्रेणी तक
8. कार्य पूर्ण करने की अवधि :- T0110 & T0111 हेतु 03 माह एवं T0112 हेतु 01 माह वर्षा ऋतु सहित।

एन आइ टी क्र. निविदा कं.	कार्य का नाम No of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रू.में) बैंक साल्वेंसी (रू.में)
1	2	3
29 T0110	PETTY BAZAR SUPPLY IN KUTCHERY SECTION UNDER CONSTRUCTION SUB DIVISION NO.-2, RAIPUR (प्रथम आमंत्रण)	5.00 5,000.00 75,000.00
29 T0111	WHITE WASHING, COLOUR WASHING IN RESI. & NON RESIDENTIAL BUILDING AT KUTCHERY SECTION UNDER SUB DIVISION NO.-2 RAIPUR (प्रथम आमंत्रण)	19.00 14,250.00 2,85,000.00
29 T0112	INTERIOR BEAUTIFICATION AND FURNISHING WORK OF SHIVNATH, HASDEV, ARPA, PAIRI AND WITH CONNECTING VARANDA AT MAIN BANGLOW RAJBHAWAN RAIPUR (प्रथम आमंत्रण)	20.00 15,000.00 3,00,000.00

निविदा संबंधी शर्ते विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-2
रायपुर (छत्तीसगढ़)

जी-07442/5

बंद हुई राजीव युवा मितान क्लब योजना

- **मंत्री टंकराम ने कहा- अपनों को लाभ पहुंचाने बनाई गई थी स्कीम**

रायपुर। कांग्रेस सरकार की एक और योजना राज्य की भाजपा सरकार ने बंद कर दी है। इस बार सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को खत्म कर दिया है। इस संबध में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी।

बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की थी। योजना अंतर्गत प्रति तिमाही प्रति क्लब 25 हजार प्रदाय किया जा रहा था। यह राशि राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति से अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा नगर निगम आयुक्त के चालू खाते में ट्रांसफर की जाती थी।

सरकार ने योजना के उद्देश्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकसित करने, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान से जोड़ना, खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना जैसी बातों को शामिल किया गया था। लेकिन जानकार बताते हैं कि इस योजना का एकमेव उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद प्रदान करना था।

राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब योजना अंतर्गत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया था। राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के 13 हजार 269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। कांग्रेस शासन काल में योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। इसमें हर क्लब में 20 से 40 युवा थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए थे। हर क्लब को प्रति तीन महीने में 25 हजार रुपये का अनुदान राशि दिए जाने का प्रविधान था। बता दें कि इससे पहले इस योजना के तहत दी जाने वाल राशि पर रोक लगाई गई थी। अब योजना को ही बंद कर दिया गया है।

मोदी सरकार कलंक से बाल बाल बची

हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को शाम आठ बजे झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ गठबंधन के नए नेता चंपई सोरेन भी गए थे, जिन्होंने 43 विधायकों के समर्थन की चिठ्ठी सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया, लेकिन चंपई सोरेन को 28 घंटे बाद सरकार बनाने का न्योता दिया और 40 घंटे बाद उनकी शपथ हुई। चालीस घंटे पहले चंपई सोरेन ने राजभवन से बाहर निकलते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, और हमने सरकार बनाने के लिए 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंप दिया है। उन्होंने यह भी बताया था कि उन्हें 4। विधायकों का समर्थन है, लेकिन चार विधायक अभी अस्पताल में हैं। जिस तरह बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नीतीश कुमार के दावे की चिठ्ठी मिलते ही उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया था, उसी तरह झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी करना चाहिए था। जबकि सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को तुरंत न्योता नहीं दिया। राज्यपाल ने अगली व्यवस्था तक हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने को भी नहीं कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें राजभवन से बाहर निकलते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना है। जब राज्यपाल ने चंपई सोरेन को न्योता नहीं दिया तो उन सभी 43 विधायकों ने राज्यपाल से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें इजाजत नहीं दी तो उन सभी ने राज भवन के सामने जाकर परेड भी की। तब राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शाम साढ़े पांच बजे पांच विधायकों के साथ मिलने को बुलाया, लेकिन इस मुलाक़ात में भी राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। इसी बीच झारखंड के भाजपा सांसद निशीकांत दूबे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 18 विधायक चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए राज्यपाल को अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति राज की सिफारिश करनी चाहिए। यह बात सही है कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, या किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चे से संस्थापक सदस्यों में से हैं और 5 बार के विधायक हैं, इसलिए उनके नाम पर किसी के एतराज की संभावना कम ही थी। निशीकांत दूबे भाजपा नेतृत्व के काफी करीब माने जाते हैं। इसलिए उनके बयान ने झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका पैदा कर दी। झारखंड मुक्ति मोर्चे और कांग्रेस को आशंका हुई कि कहीं महाराष्ट्र की तरह झारखंड में तो दलबदल नहीं होने वाला है। हेमंत सोरेन की तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दबाव में आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा ने शिवसेना के बागी विधायकों से मिलकर एकनाथ शिंदे की सरकार बना ली थी। हेमंत सोरेन ने ईडी के दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विधायकों का बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के पास था। इसके बावजूद नए नेता चंपई सोरेन को न्योता नहीं दिया जाना कई तरह की आशंका पैदा कर रहा था। खरीद फरोख्त से दलबदल करवाने की आशंका को देखते हुए गठबंधन को अपने विधायकों को कांग्रेस शासित तेलंगाना ले जाने का फैसला करना पड़ा। वह तो गनीमत है कि मौसम खराब होने के कारण फ्लाईट नहीं उड़ी और कुछ देर बाद ही राज्यपाल ने चंपई सोरेन को बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दे दिया।

कांग्रेस और सहयोगी दलों की भावना

रमेश सराफ धमोरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए देश के 28 प्रमुख विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ने का संकल्प जाहिर किया था। कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। मगर गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों की ताकत भी कम नहीं है। क्षेत्रीय दल भी अपने-अपने प्रदेशों में मजबूत स्थिति में है। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प मिला था। लगने लगा था कि आने वाले समय में यह गठबंधन भाजपा को टक्कर दे सकता है।

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने लगा वैसे-वैसे ही क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कांग्रेस से सीटों का बंटवारा करने की बात करने लगे। मगर कांग्रेस पार्टी पहले कर्नाटक व हिमाचल विधानसभा चुनाव में व्यस्तता की बात कहती रही। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बहाने बात को टाल दिया। कांग्रेस के चलते इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में आपसी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को छोड़कर बाकी तीनों प्रदेशों में चुनाव हार गई। उसके बाद भी कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे को लेकर बात आगे नहीं बढ़ायी।

इसी के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी वहां कांग्रेस को मौजूदा दो सीट बहरामपुर व दक्षिण मालदा ही देना चाहती है। जबकि कांग्रेस वहां 10 सीटों पर दावा कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बहुत कमजोर है। ऐसे में उनकी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती। इसलिए वह कांग्रेस को दो से अधिक सीट नहीं देगी। इसके अलावा ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के साथ किसी तरह का सीट बंटवारा या समझौता भी नहीं करना चाहती है। ममता बनर्जी की एक तरफा घोषणा से इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ा है। वहां कांग्रेस व वामपंथी दल बिना ममता बनर्जी के प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे।

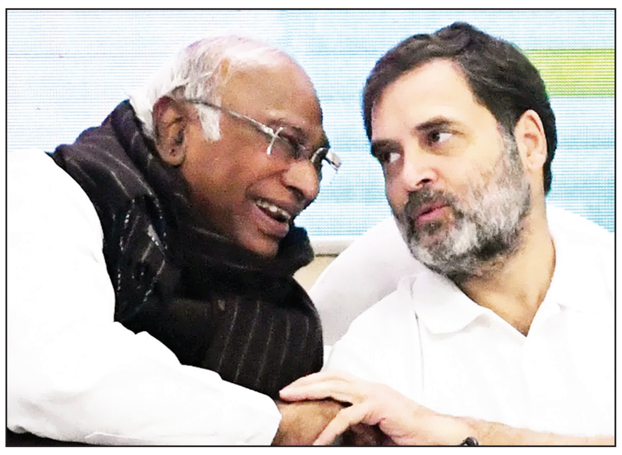

सीटों पर तालमेल नहीं होने के चलते ही इंडिया गठबंधन के शिल्पकार व प्रमुख स्तंभ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पुन: भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली है। नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के बजाय कांग्रेस पर अधिक निशाना साधा है। नीतीश कुमार का कहना है कि कांग्रेस के नेता मनमाने ढंग से गठबंधन को चलाना चाहते हैं। जिसके चलते उन्होने गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ जाने में ही जदयू की भलाई समझी।

बिहार भाजपा के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा ने वहां 17 सीटे जीती थी। मगर वर्तमान में भाजपा सबसे कमजोर स्थिति भी बिहार में ही नजर आ रही थी। मगर नीतीश कुमार के पुन: भाजपा से जुड़ने के चलते बिहार में एक बार फिर भाजपा के मजबूत होने की संभावना लगने लगी है। इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाना भी नीतीश कुमार के जाने का एक बड़ा कारण रहा है।

नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। मगर कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त करवा दिया था। जिससे नीतीश कुमार मन ही मन खुन्नस खाए हुए थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जिसके चलते उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने जा रही है। इसलिए उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाना ही बेहतर समझा।

उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए ग्यारह सीट व राष्ट्रीय लोकदल के लिये सात सीट छोड़कर बाकी 62 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाने की घोषणा कर दी है। जबकि कांग्रेस वहां 20 सीटों पर दावेदारी जता रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास अभी एक मात्र रायबरेली की सीट है। जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वहां मात्र 6.31 प्रतिशत ही वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा था। वहां पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को 2.33 पतिशत ही वोट मिल पाये थे। कांग्रेस वहां अकेले ही चुनाव लड़ेगी तो स्थिति बहुत कमजोर रहेगी।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अपने प्रभाव वाले प्रदेशों में भी साथी दलों के लिए कुछ सीटें छोड़े। जिससे उनके प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ सकें। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा में आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। जिसके चलते आम आदमी पार्टी चाहती है कि गोवा व गुजरात में कांग्रेस उनके लिए कुछ सीट छोड़ें। बदले में दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीट दे सकती है। मगर कांग्रेस चाहती है कि पंजाब में अधिक सीटों पर वह लड़े। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है।

बिहार में कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, भाकपा, माकपा के साथ ही अन्य दलों के साथ समझौता करना पड़ेगा। इसी तरह झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार आज भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गयी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को अघाड़ी में शामिल दलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीटों के बंटवारे की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

विपक्ष में सबसे बड़ा दल होने के चलते कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वह अपने साथ इंडिया गठबंधन में शामिल सभी छोटे-बड़े दलों को जोड़कर उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें सम्मानजनक स्थिति प्रदान करें। ममता बनर्जी, भगवंत मान, अखिलेश यादव की सीट बंटवारे पर एकतरफा घोषणा करने व नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को इस बात पर चिंतन मनन करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों क्यों बन रही है जिसके कारण नीतीश कुमार जैसे मजबूत नेता को इंडिया गठबंधन छोड़ना पड़ा। भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से ना बने जिससे उनके किसी अन्य सहयोगी को भी गठबंधन से अलग होना पड़े। इस बात की पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी को लेनी होगी। बहरहाल तो नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन में टूट का जो सिलसिला शुरू हुआ है। उसका नतीजा क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

हे पुत्र! तुम उनसे सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शुकदेव जी सुमेरु-पर्वत से उतर कर समतल भूखण्ड पर आये और महाराज जनक के द्वारा संरक्षित मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। तदनन्तर शुकदेव मुनि को आया हुआ देखकर द्वारपालों ने राजा जनक को यह संदेश दिया कि हे राजन्! राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र श्रीशुकदेव जी आपसे मिलने के लिए आये हैं, उन (शुकदेव) मुनि की परीक्षा के लिए महाराज जनक ने अवज्ञापूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि वे वहीं पर रुकें, इतना कहने के उपरान्त राजा सात दिनों तक पूरी तरह से शान्त रहे। इसके पश्चात् उन्होंने शुकदेव मुनि को अपने राज-प्राङ्गण में आमन्त्रित किया और वहाँ भी वे सात दिनों तक उसी तरह शान्त रहे।

इसके अनन्तर राजा ने उन्हें अपने अन्त:पुर के आँगन में ससम्मान बुलवाया तथा वहाँ पर भी सात दिनों तक वे उनके समक्ष नहीं आये। विदेहराज जनक ने अन्त:पुर में युवती स्त्रियों, विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान एवं भोज्य पासहित उन श्रेष्ठ मुनि शुकदेव जी का स्वागत-सत्कार किया। वे समस्त भोग एवं भोज्य सामग्री उन व्या रुदेव जी के मन को ठीक वैसे ही नहीं डिगा सके, जैसे कि मन्द मन्द प्रवाहित पवन दृढ़तापूर्वक प्रांत हुए पर्वत को गतिशील नहीं कर सकता। वहाँ उस अन्त: पुर में ज्ञानी शुकदेव जी असङ्ग, समभाव वाले, निर्मल एवं पूर्णचन्द्र के सदृश प्रतिष्ठित बने रहे। इस प्रकार जब राजा जनक ने श्रीशुकदेवजी के चरित्र की भली-भाँति परीक्षा ले ली, तब उन्हें अपने समीप बुलाया। उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार करते हुए बोले- हे शुकदेव जी! आपने अपने सांसारिक कृत्यों को समाप्त कर दिया है तथा आपको सभी मनोरथ प्राप्त हैं, कृपया बताने का अनुग्रह करें कि अब आपकी क्या अभिलाषा है? **क्रमश: ...**

गरीबी रेखा के नीचे लेकिन इंसानियत में सबसे आगे

भले ही उनकी आय कम है, वे घरों में झाड़ू-पोंछा लगाकर अपने परिवार की आजीविका चलाती हैं, लेकिन किसी की मदद करने में उनका दिल बड़ा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विदिशा में घरों में झाड़ू-पोंछा लगाने वाली महिलाओं ने, जिनके परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, स्वेच्छा से चंदा एकत्र कर पीएम केयर फंड में 41 हजार रुपये का योगदान किया।

हालाँकि यह रकम कोई बहुत बड़ी नहीं है पर एक बड़ी प्रेरणा अवश्य है, जो इन महिलाओं की अपने देश और समाज के प्रति गहरी भावनाओं को दर्शाती है। बीपीएल परिवारों की इन महिलाओं की इसी बड़ी सोच ने इस छोटी सी राशि को कहीं अधिक बड़ा बना दिया है। हर ओर इसकी प्रशंसा हो रही है।

महामारी से बचाव के लिए कई उद्योगपति से लेकर समाजसेवी संगठन आर्थिक रूप से मदद के लिए आगे आये हैं। किंतु इस तरह के प्रयास यह दिखाते हैं कि गरीब वर्ग भी अपने स्तर पर कोरोना पीड़ितों की मदद में पीछे नहीं है। संकट के दौर में जब झाड़ू-पोंछा करने वाली इन महिलाओं का काम भी बंद हो चुका है, इसके बावजूद अपनी बचत में से कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आकर इन्होंने कमाल का जज्बा दिखाया है। इनमें से एक सुनीता रैकवार का कहना था कि इस महामारी से बचाव के लिए सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ी मदद तो हम कर ही सकते हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने अन्य महिलाओं से बातचीत की। जिसमें सभी ने एक बार में ही सहमति दे दी। किसी ने 20 रुपये तो किसी ने 100 रुपये तक की मदद की। इस तरह करीब 200 महिलाओं ने 41 हजार रुपये की राशि जमा की। शुक्रवार को 41 हजार रुपये की राशि का चेक पीएम केयर फंड के नाम डिप्टी कलेक्टेट प्रवीण प्रजापति को सौंपा। एक अन्य महिला गुड्डी वंशकार ने बताया कि सभी 200 महिलाएँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित हैं।

ऐतिहासिक फैसलों से लोकतंत्र हुआ मजबूत

जयसिंह रावत

अपने सात दशकों के जीवनकाल में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में सहायक रहा है। ऐतिहासिक निर्णयों ने इन अधिकारों के दायरे को स्पष्ट और विस्तारित किया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में योगदान मिला है।

गणतांत्रिक भारत के सबसे बड़े न्याय का मंदिर ''सर्वोच्च न्यायालय'' अपने 75 वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इन सात से अधिक दशकों में सर्वोच्च न्यायालय के तहत हमारी न्यायपालिका ने भारतीय लोकतंत्र को आकार देने और इसे बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखने, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके निर्णयों का भारतीय लोकतंत्र के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। संविधान के संरक्षक के तौर पर देशवासियों की अटूट आस्था अर्जित कर अदालत के साथ ही न्याय के मंदिर के रूप में भी स्वयं को स्थापित किया है।

चूंकि अभी-अभी हमने गणतंत्र दिवस पर अपने देश की सात दशकों की लम्बी यात्रा को याद किया इसलिए सर्वोच्च न्यायलय की हीरक जयन्ती पर इसकी जीवन यात्रा का स्मरण करना भी जरूरी है। भारत के एक प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद 28 जनवरी, 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जिसमें भारत की संसद भी थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संघीय न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुनदास और न्यायमूर्ति सैय्यद फजल अली, एम. पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी और एस. आर. दास को पद की शपथ दिलाई थी। हरिलाल कानिया ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 1950 से 1951 तक सेवा की।

न्यायमूर्ति अन्ना चांडी 1959 में भारत में उच्च न्यायालय (केरल उच्च न्यायालय) के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थीं। संसद भवन के नरेंद्र मंडल में, भारत का संघीय न्यायालय 1937 और 1950 के बीच 12 वर्षों तक चला। संघीय न्यायालय का गणतांत्रिक भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। अपने वर्तमान भवन में 1958 में स्थानांतरित होने तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उद्घाटन के बाद संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू कीं। भवन का आकार न्याय के तराजू की छवि के रूप में बनाया गया है। भवन की केंद्रीय विंग तराजू की मुख्य बीम है। 1979 में, परिसर में दो नई विंग 'पूर्वी विंग और पश्चिमी विंग' जोड़ी गई। भवन की विभिन्न विंगों में कुल मिलाकर 19 न्यायालय कक्ष हैं। मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय केंद्रीय विंग के केंद्र में स्थित न्यायालयों में से सबसे बड़ा है। 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अवर न्यायाधीशों के साथ की गई थी जबकि इस संख्या को बढ़ाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश एक साथ बैठकर अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों की सुनवाई करते थे। जैसे-जैसे न्यायालय का कार्यभार बढ़ता गया और बकाया मामले बढ़ने लगे। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 तक बढ़ाकर, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु के होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

अपने सात दशकों के जीवनकाल में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में सहायक रहा है। ऐतिहासिक निर्णयों ने इन अधिकारों के दायरे को स्पष्ट और विस्तारित किया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में योगदान मिला है।

न्यायालय ने सार्वजनिक हित और महत्व के मुद्दों को संबोधित करने में न्यायिक सक्रियता प्रदर्शित की है। जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से, अदालत ने बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने वाले मामलों का संज्ञान लिया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप हुआ है। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों को बरकरार रखने, कार्यकारी कार्यों पर संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देने और आपात स्थिति के दौरान भी सरकारी शक्ति की सीमित प्रकृति पर जोर देने वाले फैसले दिए।

चुनावी मुद्दों को संबोधित करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्रिय रहा है। इसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग, राजनीतिक उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर निर्णय दिए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने में सक्रिय रहा है। उदाहरण के लिए, इसने ताज-महल को प्रदूषण से बचाने के उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वायु और जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए। न्यायालय ने सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया है और ऐसे निर्णय दिए हैं जिन्होंने सामाजिक सुधारों में योगदान दिया है।

न्यायालय ने समानता के सिद्धांतों के साथ सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को संतुलित करते हुए, आरक्षण नीतियों से संबंधित मुद्दों से निपटा है। इसने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा पर दिशानिर्देश और सीमाएं निर्धारित की हैं। सन् 2019 में अयोध्या भूमि विवाद के समाधान ने अत्यधिक संवेदनशील और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने की अदालत की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे एक ऐसे मामले का कानूनी समाधान मिला, जिसका सांप्रदायिक सद्भाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

अदालत के कुछ ऐतिहासिक फैसले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के बाद से देश के कानूनी और न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) का मामला व्यक्तियों की निवारक हिरासत से संबंधित था और इसमें संविधान के सुरक्षात्मक प्रावधानों के संबंध में ''संकीर्ण नियम'' का सिद्धांत निर्धारित किया गया था।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) जैसे ऐतिहासिक मामलों ने संवैधानिक संशोधनों की शक्ति को सीमित करते हुए बुनियादी संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया। पीआईएल की अवधारणा एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के मामले में पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ सहित विभिन्न मामलों में भोपाल गैस त्रासदी के कानूनी परिणामों से निपटा। मुआवजे के मुद्दों को निपटाने में अदालत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शाहबानो मामला मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार से जुड़ा था और समान नागरिक संहिता पर बहस छिड़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाद में सरकार ने कानून बनाकर पलट दिया था। अयोध्या भूमि विवाद मामला भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले मामलों में से एक था।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित स्थल को हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित किया गया और मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए जमीन का वैकल्पिक हिस्सा प्रदान किया गया।

आज का इतिहास

1815 विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विटजरलैंड में खोला गया।
1830 लंदन प्रोटोकॉल में ग्रीस की संप्रभुता की पुष्टि हुई थी।
1834 वेक वन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी।
1852 प्लैटिनम युद्ध बायान गठबंधन में अर्जेंटीना कॉन्फेडरेशन को पराजित किया गया था जिसमें ब्राज़ील, उरुग्वे और एंट्रे रोस और कोरिएंटेस के अरजेंटाइन प्रांत शामिल थे।
1860 थॉमस क्लेसन ने प्रथम अमरीकी अधीक्षक कृषि के रूप में पदभार ग्रहण किया।
1870 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पंद्रहवें संशोधन को जाति, रंग या सेवा की पूर्व स्थिति की परवाह किए बिना नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया था।
1913 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सोलहवां संशोधन की पुष्टि की गई थी, जिससे अमेरिकी कांग्रेस को राज्यों के बीच अपील किए बिना या जनगणना के परिणामों पर आधारित बिना एक आयकर लगाने की अनुमति मिली।
1934 पहली बार हवाई जहाजों से पार्सेल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। आज यह कंपनी लुफ्थांसा के नाम से जानी जाती है।
1954 एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले पहले सत्ताधारी राजा बने।
1959 अमेरिकी रॉक एंड रोल संगीतकार बडी होली, रिची वैलेंस और जेपी द बिग बोपर रिचर्डसन की मौत हो गई जब उनका विमान मेसन सिटी म्यूनिसिपल एयरपोर्ट इयोवा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
1962 क्यूबा के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंध की घोषणा की।
1972 ईरान में खतरनाक बर्फानी तूफान शुरू हुआ, इसमें 4 हजार मारे गए।
1986 पिक्सर एनीमेशन स्टूडियो कैलिफोर्निया में खोला गया।
1994 विलियम जे पेरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई।
1994 जीन क्लाउड वैन डैममे एक अभिनेता हैं जो बैंकॉक में 28 साल के डार्सी लापियर की 32 साल की उम्र है।
1994 अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी व्यापार को गले लगा लिया।
1995 अंतरिक्षयात्री आईलीन कॉलिन्स अंतरिक्ष शटल को संचालित करने वाली पहली महिला बनीं।
1998 बॉब वाटसन के महाप्रबंधक को न्यूयॉर्क यांकीज़ द्वारा ब्रेन कैशमैन के साथ बदल दिया गया था।
2007 इराक की राजधानी बगदाद के एक बाज़ार में हुए बम विस्फोट में 135 लोगों की मौत।
2010 सोमालियाई समुद्री लुटेरों द्वारा यमन के दक्षिण में एक उत्तर-कोरियाई ध्वजवाहक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया गया।

कल्पना के बजाय चंपई के मुख्यमंत्री बनने की अंतर्कथा

आलोक कुमार

जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन के नीचे से सरककर बुजुर्ग नेता चंपई सोरेन के पास पहुंच गई है। 68 साल के चंपई सोरेन के चयन की वजह झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के परिवार में मचा विद्रोह रहा। मुसीबत में फंसे हेमंत सोरेन आपात स्थिति में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बना चाहते थे, ताकि राजनीतिक विरासत की बागडोर उनके हाथों से बंधी रहे। लेकिन शिबू सोरेन की बड़ी बहू व विधायक सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के छोटे भाई व विधायक बसंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास के सख्त खिलाफ रहे। इस नाराजगी से झामुमो में टूट होने की आशंका बढ़ गई थी। इसलिए न चाहते हुए भी जेल जाते हेमंत सोरेन को पत्नी कल्पना के नाम से पीछे हटना पड़ा।

उनकी जगह जो चंपई सोरेन झामुमो विधायक दल के नवनियुक्त नेता चुने गये हैं, वो 1991 में पहली बार सरायकेला से निर्दलीय विधायक बने थे। चंपई सोरेन अलग झारखंड आंदोलन के दिनों में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के संपर्क में आए और संघर्ष के साथी बने रहे।

पहली बार चंपई सोरेन को मंत्री बनने का मौका झामुमो के साथ बनी भाजपा की अर्जुन मुंडा सरकार में मिला। संयोगवश भाजपा नेता अर्जुन मुंडा के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी झामुमो विधायक के तौर पर हुई थी। तब मुंडा को झामुमो का टिकट दिलाने में झारखंड टाइगर के नाम से कोल्हान में मशहूर चंपई सोरेन की ही भूमिका थी। बाद में मुंडा भाजपा में शामिल हो गये। चंपई सोरेन की तरह ही अर्जुन मुंडा भी ओडिशा व बंगाल से लगने वाले

कोल्हान क्षेत्र से ही आते हैं। मूल रूप से उत्तरी छोटानागपुर के हजारीबाग जिला से आने वाले झामुमो सुप्रीमो के परिवार ने दक्षिण कोल्हान से दूर उत्तर में बिहार और पूर्व में बंगाल से लगे संथाल परगना में पांच दशकों से राजनीतिक आधार बना रखा है। झारखंड में स्थायी प्रभाव की तलाश में प्रतिद्वंदी भाजपा लगातार संथाल परगना में मजबूत शिबू सोरेन के गढ़ को ही ध्वस्त करने की कोशिश में है। भाजपा के जोरदार प्रयासों का नतीजा है कि शिबू सोरेन पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा सांसद सुनील सोरेन के हाथों हार चुके हैं और फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं।

झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की राजनीति में खास अहमियत संथाल परगना की वजह से है। 1998 लोकसभा चुनाव में दुमका सीट से उन्होंने शिबू सोरेन को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचने के मंसूबे को साकार किया था। इनाम स्वरूप वाजपेयी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया और 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी भाजपा की ओर से प्रथम मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन परिवार के तीनों विधायक संथाल परगना से आते हैं। स्वयं शिबू सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में फंसकर जब सांसदी गंवानी पड़ी तो उन्होंने इसी संथाल परगना के दुमका से पत्नी रूपी सोरेन को लोकसभा चुनाव लड़वाना पसंद किया। लिहाजा यह पहला मौका है कि आंतरिक पारिवारिक कलह से मजबूरी में फंसे शिबू सोरेन को न केवल अपने परिवार के बाहर से बल्कि अपनी राजनीतिक पकड़ वाली जमीन के बाहर से किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में ढूंढना पड़ा है। राजनीति में शिबू सोरेन के असली वारिस के तौर पर बड़े पुत्र विधायक दुर्गा सोरेन सक्रिय थे। 2009 में दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से उनकी पत्नी सीता सोरेन दिवंगत पति की पारंपरिक जामा विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मगर घर में हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की वजह से लगातार खफा भी चल रही हैं। विधायक सीता सोरेन की नाराजगी का नतीजा है कि उनकी दोनों पुत्रियों राजश्री और जयश्री सोरेन ने दिवंगत पिता का स्थान पाने के लिए बीते तीन साल से दुर्गा सोरेन सेना नामक मंच बना रखा है।

हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश का हेमंत की विधायक भाभी सीता सोरेन ने ही स्पष्ट विरोध नहीं किया, बल्कि हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन ने भी भाभी कल्पना सोरेन की राह में काटें बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी मौका आया उन्होंने जताने में कमी नहीं छोड़ी कि परिवार में उनकी जगह कल्पना सोरेन से ऊंची है।

पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को पारंपरिक दुमका विधानसभा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। उपचुनाव में उन्हें संथाल परगना की बरहेट विधानसभा सीट से जीतकर आना पड़ा। मौजूदा विधानसभा चुनाव उन्होंने दो सीटों अर्थात दुमका और बरहेट दोनो से लड़ा और जीता। दो में से एक सीट से इस्तीफ़ा देने की बाध्यता में उन्होंने दुमका सीट खाली की। उपचुनाव में दुमका सीट से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, मगर हेमंत सोरेन को पत्नी की बजाय भाई बसंत सोरेन को दुमका सीट से उतारना पड़ा। जमीन घोटाले की जांच में गला फंसता देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपात स्थिति का अंदाजा हो चला था। इसीलिए गिरफ्तारी और पद से इस्तीफे की आशंका को परखते हुए अल्पसंख्यक बहुल गांडेय विधानसभा सीट को तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद से खाली करा लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर गैर विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा सके और उपचुनाव के जरिए छह महीने में विधानसभा सदस्य होने की संवैधानिक बाध्यता भी पूरी की जा सके। खास डीलिंग के तहत विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ही शिबू सोरेन परिवार की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई। नतीजा, सबके विरोध के बाद परिवार की बहू कल्पना के बजाय परिवार के बाहर से आनेवाले चंपई सोरेन को सीएम पद के लिए चुना गया जो कद्दावर नेता तो हैं ही, शिबू सोरेन के भी विश्वासपात्र हैं।

एम फैक्टर से भाजपा ने तैयार की लोकसभा चुनावों की पिच

आशीष तिवारी

मोदी सरकार के अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर के साथ लोकसभा के चुनावों की पूरी पिच तैयार कर दी। इसमें कुल तीन करोड़ लखपति दीदी की घोषणा से लेकर दो करोड़ घर बनाने का एलान शामिल है। जबकि तीसरी और महत्वपूर्ण घोषणा के तौर पर गंभीर बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू किया जाने वाला नि:शुल्क टीकाकरण है। सियासी जानकार जहां प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के इस बजट को साइलेंटली गेम चेंजर बता रहे हैं। वहीं अर्थशास्त्रियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों की नजर में यह बजट कई मायनों में सबसे अलग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान जिन महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात की, उसमें लखपति दीदी योजना शामिल है। इसके अलावा महिलाओं पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में आशा वर्कर आंगनबाड़ी सेविकाओं और हेल्पर को भी शामिल किए जाने की घोषणा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर करुणानाथ कहते हैं कि महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ-साथ सशक्त बना कर न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि समाज में सकारात्मक विकास की बात भी होती है। यह योजना सियासी नजरिए से क्या असर दिखाएगी वह अलग बात है। लेकिन समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आर्थिक मामलों की जानकार मुनिशंकर कहते हैं कि महिलाओं के लिहाज से इस बजट में केंद्र सरकार ने काफी कुछ दिया है। इसमें लाखों आशा वर्कर समेत आंगनबाड़ी से जुड़ी लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर भी फायदा हो रहा है। उनका कहना है लखपति दीदी योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रहीं हैं। इसके तहत अभी जितनी महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने का फायदा मिला है, वह आसपास की अन्य महिलाओं पर भी सकारात्मक असर डाल रहा है। शंकर कहते हैं कि तीन करोड़ महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाने से इसका असर कई गुना ज्यादा देखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक ओपी मिश्रा कहते हैं कि सियासी नजरिए से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने का दांव भाजपा के लिए बड़े साइलेंटली गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा सकता है। मिश्रा के मुताबिक इस योजना को आगे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के शामिल करने से न सिर्फ महिलाओं का ही डेवलपमेंट होता है, बल्कि पूरे परिवार का विकास शामिल है। वह कहते हैं कि लखपति दीदी योजना के 360 डिग्री वाले आयामों को देखते हुए ही इसे आगे बढ़ाया गया है। उनका अनुमान है कि लखपति दीदी योजना के दायरे को तीन करोड़ की संख्या से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ओपी मिश्रा मानते हैं कि लखपति दीदी योजना से मोदी सरकार को बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ी डॉक्टर पुष्पा जयसवाल रहती है कि सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जो योजना शुरू करने की बात बजट में कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर की एक प्रमुख वजहों में शामिल है। वह कहती है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों के मुताबिक इस बात का पता चलता है कि भारत में भी इस बीमारी से न सिर्फ मौतें हो रहीं हैं, बल्कि महिला मरीजों का प्रतिशत भी बढ़ा है। गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े डॉक्टर का मानना है कि जागरूकता के चलते महिलाएं सजग हो रही हैं। लेकिन समय रहते अगर इसका टीकाकरण किया जा सके तो इस खतरनाक और गंभीर बीमारी को वक्त से पहले रोका जा सकेगा। अब जब केंद्र सरकार ने अपने बजट में निशुल्क टीकाकरण शुरू करने की बात कही है, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ा और सराहनीय कदम ही है।

राजस्थान से सोनिया को राज्यसभा भेजने की चर्चा

राहुल संपाल

राजस्थान में तीन सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से हाईकमान फैसला करेगा। वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से भी एक नाम सबको चौंका सकता है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की उम्मीदवार बन सकती हैं या उनके अलावा कोई दिग्गज नेता राजस्थान से उच्च सदन में जाएगा। दरअसल, राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने फिर से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की इच्छा कांग्रेस नेतृत्व के सामने जता दी है। खाली हो रही एक सीट पर पार्टी किसी दिग्गज नेता को उच्च सदन भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों की मानें तो सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। पार्टी राजनीतिक समीकरण के आधार पर तय करने में जुटी है कि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया जाए या फिर राजस्थान से। यूपी की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी चल रही है। पार्टी की सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने के बजाय राज्यसभा चुनाव के जरिए सांसद बनाए रखने की इच्छा जताई है। इधर, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया कि वे तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। साथ ही, रेड्डी के इस बयान से पहले तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने भी सोनिया गांधी से तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। पार्टी सोनिया के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को भी राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है। माकन साल 2022 में राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। माकन के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अच्छे संबंध रहे हैं, हालांकि नवंबर 2022 की विधायक दल की बैठक नहीं होने देने की घटना के बाद जरूर उनके संबंधों में कुछ खटास की खबरें आई थीं। सूत्रों के अनुसार अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान ही लेगा, जो भी नाम तय करेगा, उसे लेकर अशोक गहलोत से जरूर चर्चा करेगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रभावशाली नेता के हाथ ही फ्लोर मैनेजमेंट दिया जाएगा, ताकि क्रॉस वोटिंग नहीं हो। भाजपा में भी भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने से सीट खाली होने जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक सीट पहले से खाली हो चुकी है। भाजपा में चौंकाने वाला नाम राजेंद्र राठौड़ का हो सकता है। हालांकि, संघ की ओर से सतीश पूनिया का नाम सुझाया गया है। वहीं, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह-प्रभारी अल्का गुर्जर के नाम की भी चर्चा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। यादव वहां के सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं। बाबा बालकनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण लोकसभा सीट खाली है।

पलटीमार राजनीति के चैंपियन हैं नीतीश कुमार

प्रवीण बागी

कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे,
तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे,
तब तुम मेरे पास आना प्रिय,

भाजपा के नेता आजकल नीतीश कुमार के लिए यही गाना गुनगुनाते होंगे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को अपने निकट पाकर भले ही खुश हो लेकिन बिहार के पार्टी कार्यकर्ता हतप्रभ हैं। कल तक जिसके खिलाफ वे झंडा उठाए घूम रहे थे, अब उसकी जयकार करने की मजबूरी है। पार्टी कार्यकर्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसकी परवाह किसे है? यह ठीक है की सत्ता हासिल करना राजनीतिक दलों का मूलभूत उद्देश्य होता है, लेकिन उसका भी कुछ प्रोटोकॉल होता है, एक तहजीब होती है, नीति होती है।

जनता का विश्वास हासिल कर सत्ता में आना और जनता के कल्याण के लिए सत्ता का इस्तेमाल करना ही लोकतंत्र है। लेकिन बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वह इन सबसे परे है। यह राजनीतिक अवसरवाद का निकृष्टम उदहारण है। बिहार में जो हो रहा है वह लोकतंत्र नहीं धतकर्म है। नीतीश इस धतकर्म के माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बारंबार नट की तरह सत्ता की डोर पर कलाबाजी दिखाना और गुलाटी मारना उनका स्वभाव बन गया है। यहां यह याद दिलाना जरूरी है की नीतीश इंडि गठबंधन के संस्थापक थे। उन्होंने ही घूम -घूम कर सभी विपक्षी नेताओं से बात की थी और साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। विपक्ष की पहली बैठक

उन्हीं की पहल और आमंत्रण पर पटना में हुई थी। बेशक इसके पीछे कांग्रेस की सहमति थी लेकिन पहल नीतीश की ही थी। तब उन्होंने कहा था कि वे विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम करना चाहते हैं ताकि भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाया जा सके। तब नीतीश के मन में प्रधानमंत्री की कुर्सी थी। लेकिन यह इच्छा उन्होंने खुद कभी जाहिर नहीं की लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने इसके लिए माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की। पर पीएम की कुर्सी उनसे दूर होती गई। इंडिया पर कांग्रेस ने कब्ज़ा कर लिया और नीतीश को हासिए पर ठेल दिया गया।

इसके बाद उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा पैदा हो गया। लालू प्रसाद की तरफ से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि जदयू को तोड़ कर तेजस्वी को सीएम बनाने का तानाबाना बुना जाने लगा। इसमें ललन सिंह के भी सहयोग की चर्चा जब आम हुई तो आनन-फानन में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। फिर भी सीएम पद छोड़ने का दबाव कम नहीं हुआ। उधर भाजपा पर लोकसभा की 40 में से 39 सीटों पर जीत को दोहराने का दबाव था। यह नीतीश के साथ से ही हो सकता था। उधर नीतीश सीएम की कुर्सी बचाए रखना चाहते थे। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। यही जरूरत भाजपा -जदयू को फिर से साथ लाया।

यह तो हुई अंदर की बात। नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि भाजपा में अचानक ऐसी क्या बुराई आ गई थी कि उसे छोड़ कर राजद के साथ चले गए थे? फिर अचानक भाजपा में उन्हें क्या अच्छा दिखा की फिर उसके साथ आ गए? भाजपा तो जो कल थी वही आज भी है! फिर पलटने की वजह क्या रही? इसी तरह राजद में उन्हें कौन का सतगुण दिखा की भाजपा से नाता तोड़ वे उसके संगी हो गए, फिर अचानक क्या दुर्गुण दिखा की कन्नी काट लिए ? यह कौन सा खेल है नीतीश जी? कल तक नीतीश कुमार में दुनिया का हर दुर्गुण देखने वाली, उन्हें बीमार और मानसिक रोगी बतानेवाली भाजपा को भी यह बताना चाहिए कि रातोरात नीतीश जी में उन्हें क्या सुधार दिखा की पुनः उनके आज्ञाकारी सहयोगी बन गए हैं? यह कैसी पॉलिटिक्स है?

जहानाबाद के उस कार्यकर्ता की आत्मा को भाजपा नेता क्या मुंह दिखाएंगे जिसकी मौत पटना में भाजपा के प्रदर्शन में पुलिस की पिटाई से हुई थी? उस लाठी चार्ज को जदयू और राजद जायज ठहरा रहे थे। भाजपा अब किस मुंह से उसकी आलोचना करेगी? भाजपा नेता कार्यकर्ताओं को अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार का जो सपना दिखाते आ रहे थे, उस सपने का क्या होगा? क्या यह माना जाए की कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा था? सत्ता लोलुपता के सन्दर्भ में भाजपा, जदयू या राजद में कोई अंतर दिखता है क्या ?

पाला बदल कर नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सर्वाधिक लम्बे काल तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम जरूर दर्ज हो गया है। लेकिन इस बाजीगरी से बिहार की प्रतिष्ठा गिरी है। नेताओं की विश्वसनीयता पेंदे में चली गई है। ऐसी पलटीमार राजनीति से बिहार का कोई भला होनेवाला नहीं है। सबसे बड़ा संकट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सामने आ खड़ा हुआ है। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने केसरिया पगड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि यह पगड़ी नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद ही खोलेंगे। नीतीश ने ऐसी कलाबाजी दिखाई कि सम्राट ने जिसको हटाने का संकल्प लेकर पगड़ी बंधी थी उसी के नेतृत्व में वे उप-मुख्यमंत्री बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कोर टीम की बैठक में उन्होंने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। उन्होंने पूछा की अब वे क्या करेंगे ? बताते हैं की वे इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उन्हें पार्टी के फैसले को मानना पड़ा।

भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया की जनसभा में घोषणा की थी कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। यह बात उन्होंने तीन बार दोहराई थी। लेकिन नीतीश तो बाजीगर हैं। उनके पास हर दरवाजे की चाभी रहती है। जब चाहते हैं अपनी सुविधानुसार दरवाजे खोल लेते हैं।

विपक्षी एकता के लिए मनहूस है राहुल गांधी की न्याय यात्रा

अजय सेतिया

राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा ने जो प्रभाव पहले दिन से ही छोड़ा था, वैसा प्रभाव इस बार की न्याय यात्रा में एक पखवाड़े के बाद भी दिखाई नहीं दिया। उनकी यात्रा 14 जनवरी को शुरू हुई और जनवरी में ही इंडी एलायंस को दो बड़े झटके लग गए। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा कर इंडी एलायंस छोड़ दिया, फिर झारखंड में उनके प्रवेश से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गए। राहुल गांधी जब बिहार में थे तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से ईडी लैंड फॉर जॉब घोटाले में कड़ी पूछताछ कर रही थी। अब जब वह दुबारा बिहार में घुसेंगे, तब तक तेजस्वी और लालू यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पहले दिन से उनकी यात्रा इंडी एलायंस के लिए मनहूस साबित हो रही है। शुरू से ही विवादों में भी घिरी रही, क्योंकि मणिपुर सरकार ने उन्हें संवेदनशील इलाकों से गुजरने की इजाजत नहीं दी। फिर असम में भी वैसा ही हुआ, जब श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय वह शंकरदेव के जन्म स्थान पर जाना चाहते थे। शंकरदेव ट्रस्ट ने उन्हें सुबह के बजाए शाम को आने को कहा क्योंकि उस दिन सैकड़ों हिन्दू श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए जमा थे। राहुल गांधी ने इसे सरकार की तरफ से उन्हें रोके जाने का आरोप लगा कर दो घंटे का धरना दे दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने तय रूट से अलग रूट पकड़ लिया और पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। असम पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, उस घटना ने उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया। अगर उस दिन यह घटना न होती और असम के मुख्यमंत्री प्रेस कांफ्रेंस करके राहुल गांधी पर टिप्पणी न करते, तो उससे पहले आठ दिन तक वह अखबारों में कहीं भी सुर्ख़ियों में नहीं थे।

असम के बाद जब वह बंगाल में दाखिल हुए तो ममता बनर्जी ने उन्हें उन क्षेत्रों में यात्रा की इजाजत नहीं दी, जहां से वह गुजरना चाहते थे। कांग्रेस को उम्मीद तो यह थी कि ममता बनर्जी क्योंकि इंडी एलायंस में शामिल है, इसलिए वह उनके बंगाल में प्रवेश के समय खुद स्वागत करने के लिए मौजूद होंगी, लेकिन इसके ठीक उल्ट ममता बनर्जी ने एनडीए की मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार किया और दो दिन तक यात्रा रूकी ही रही। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बंगाल प्रवेश से पहले ही कांग्रेस के साथ किसी तरह का चुनावी गठबंधन करने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा वह इंडी एलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें यह सूचना तक नहीं दी कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें तो मीडिया से सूचना मिली। राहुल गांधी ने 25 जनवरी को बंगाल में प्रवेश किया था। ममता विरोधी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जैसे भाजपा शासित मणिपुर और असम में विरोध का सामना करना पड़ा वैसे ही बंगाल में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें जनसभा करने की इजाजत नहीं दी थी। मल्लिकार्जुन खरगे ने ममता बनर्जी से बात भी की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई।

सिलीगुड़ी में प्रशासन ने बच्चों की परीक्षा का बहाना बनाकर उन्हें यात्रा और जनसभा की इजाजत नहीं दी। नतीजा यह निकला कि 26-27 को यात्रा बंद करके राहुल गांधी ने 28 जनवरी से दुबारा यात्रा शुरू की और 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश किया।

राहुल गांधी के किशनगंज से बिहार में प्रवेश से 18 घंटे पहले नीतीश कुमार ने इंडी एलायंस की सरकार गिरा कर कांग्रेस और राजद को सरकार से बाहर निकाल दिया। राहुल गांधी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। यह वही नीतीश कुमार थे, जिन्होंने इंडी एलायंस को खड़ा किया और एलायंस की पहली बैठक भी पटना में होस्ट की थी। अगर उन्हें पटना बैठक में ही इंडी एलायंस का अध्यक्ष या संयोजक बना दिया जाता, तो उनके एलायंस छोड़ कर जाने की कोई संभावना ही नहीं बचती। लेकिन कांग्रेस ने लालू यादव के दबाव में आकर उन्हें संयोजक बनाने से परहेज किया। लालू यादव ने ममता बनर्जी के भी कान भरे कि संयोजक बनने का हक तो उनका है, क्योंकि वह भाजपा से मुकाबला करके लोकसभा की 22 सीटें जीत कर आई हैं, जबकि नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन और मोदी के चेहरे पर 16 सीटें जीत कर आए थे। नीतीश कुमार के कान तो 13 दिसंबर को ही खड़े हो गए थे, जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खरगे को इंडी एलायंस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उनका गुस्सा 19 जनवरी की ऑनलाईन बैठक में फूटा जब उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ था और राहुल गांधी ने कहा कि वह नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए ममता बनर्जी से बात करेंगे। नीतीश कुमार को लगा कि कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। उनके इंडी एलायंस छोड़ने के और भी कई कारण थे, जिनका खुलासा अब वह खुद और उनकी पार्टी के लोग किस्तों में कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की ओर से अपनी यात्रा के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कही गई बातों ने उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है।

राहुल गांधी ने एक बड़ी ही अजीब बात कही कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का सुझाव कांग्रेस ने दिया था। जिसके लिए नीतीश कुमार और भाजपा तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि लालू यादव और कांग्रेस के दबाव में नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना करवाई। जबकि सच यह है कि नीतीश कुमार जब एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री थे तब 18 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा ने पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाने का प्रस्ताव पास करवाया था। 27 फरवरी 2020 को फिर प्रस्ताव पास करवा कर केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि 2021 की जनगणना जाति आधारित करवानी चाहिए। इसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री को जाति आधारित जनगणना करवाने का ज्ञापन दिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी शामिल थे। इसी के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य अपने स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण करवा सकते हैं। जाति आधारित सर्वेक्षण का नोटिफिकेशन 6 जून 2022 को जारी हुआ था, जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री थे। अब राहुल गांधी का जाति आधारित जनगणना का बयान विवाद का कारण बन गया है। नीतीश कुमार ने पलट कर जवाब दिया है कि कांग्रेस कभी भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं थी, अगर वह पक्ष में थी, तो वह बताए कि उसने अपने साठ साल के शासन में करवाई गई छह जनगणनाओं में से एक भी जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाई। 2011 में विपक्ष के दबाव में मनमोहन सिंह सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई भी, तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए।

इधर राहुल गांधी बिहार में विवाद खड़ा कर गए, उधर 31 जनवरी को जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में दुबारा प्रवेश किया तो उनकी कार पर पथराव हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि राहुल गांधी की कार पर बंगाल में नहीं बल्कि सुबह जब वह बंगाल में प्रवेश कर रहे थे, तब कटिहार में पथराव हुआ था। इस स्पष्टीकरण का मतलब यह नहीं था कि वह अपने रूख में बदलाव करते हुए राहुल गांधी का बंगाल में स्वागत कर रही हैं। उन्होंने कहा यह कुछ और नहीं बल्कि ड्रामा है।

महिलाएं साबित होती हैं अच्छी मैनेजर

प्रबंधन के कुछ गुण ऐसे होते हैं, जो अधिकतर महिलाओं में ही होते हैं। कहने का अर्थ है कि मैनेजमेंट की यह कला महिलाओं को नैसर्गिक गुणों के रूप में प्राप्त होती है और कई बार से पुरुषों से ज्यादा बेहतर मैनेजर साबित होती हैं।

महिला सशस्त्रीकरण पर एक लेख लिखने के लिए मैं नेट सर्फिंग कर रही थी। यह तथ्य जानकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई कि महिलाएं ज्यादा बेहतर बॉस होती हैं। पिछले वर्ष अगस्त में न्यू यॉर्क टाइम्स ने एक बहस पेश की थी, जिसका शीर्षक था 'कोई शक नहीं- महिलाएं बेहतर बॉस होती हैं'। जब यह बात मैंने अपने सहकर्मियों के बीच रखी तो महिला सहकर्मियों ने यह एक मत से स्वीकार कर लिया कि वह पुरुषों से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में सक्षम हैं, पर मेरे पुरुष सहकर्मी इस संबंध में अपने विचार पूरी तरह स्पष्ट नहीं किए। एक भारतीय सूचना सेवा अधिकारी के अनुसार हालांकि एक महिला अव्यवस्थित स्थितियों को भी बेहतर तरीके से प्रबंध कर लेती हैं, पर अधिक दबाव के सामने वह झुक जाती हैं। पर दूसरा उनका प्वॉइंट असमंजस में डालने वाला था-यदि महिलाएं बेहतर प्रबंधक होती ही हैं, तो क्यों फॉरच्यून 500 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वालों में महिलाएं की संख्या अधिक नहीं है?

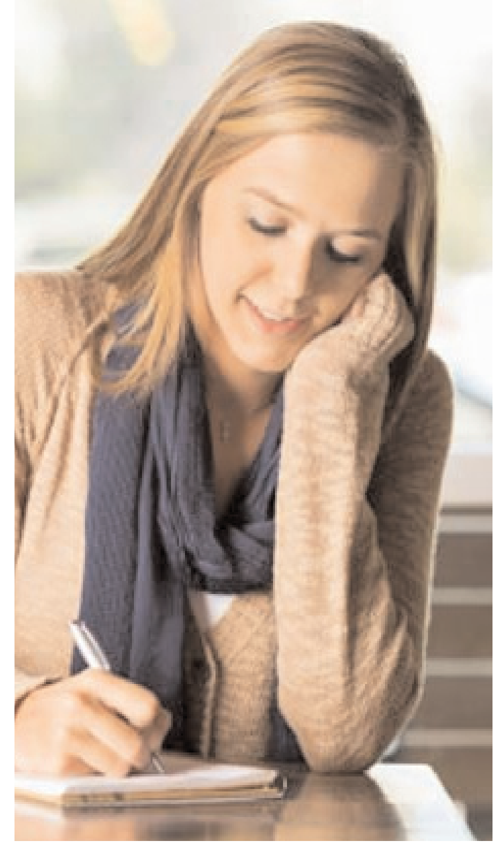

निजी अनुभव कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं बेहतर संरक्षक और सलाहकार होती हैं। शायद यही एक सबसे प्रमुख कारण है कि एचआर टीम में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। हालांकि मनोवैज्ञानिक लिंग के आधार पर अति-सरलीकरण करने से बचने की सलाह देते हैं। वो इस बात को इस तरह पेश करते हैं कि महिलाएं अच्छी टीम प्लेयर होती हैं और उनमें अधिक धैर्य होता है। पर इसे स्पष्ट और एक मत से यह कह देना कि सभी महिलाएं अच्छी प्रबंधक होती हैं, इसे पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित विचार कहा जाएगा। महिला और पुरुष दोनों के अपने निजी चारित्रिक गुण होते हैं, जिसके आधार पर ही प्रबंधकीय सफलता का अनुपात निर्धारित होता है।

कुछ ऐसे गुणों के बारे में जानते हैं, जिनमें महिलाएं आगे होती हैं-

लचीलापन - शोध कहते हैं कि जैविक तौर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मस्तिष्क का आकार छोटा होता है, परन्तु उनमें नर्व्स सेल्स अधिक होते हैं। उनके मस्तिष्क का दायां भाग अधिक सक्रिय होता है, जिससे महिलाएं आंकड़े व सूचनाएं स्थानांतरित करने में तेज होती हैं। महिलाओं में परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता अधिक होती है, इसी कारण पुरुषों की तुलना में वह एक समय में अधिक काम करने में सक्षम होती हैं।

टीम-निर्माण का गुण- वर्तमान की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बेहद जरूरी यह गुण महिलाओं में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। महिलाएं टीम निर्माण करने या टीम भावना विकसित करने में बेहतर होती हैं, क्योंकि मूलत- वह जननी और घर की देखभाल और एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनमें सहयोगात्मक भावना सबसे अधिक होती है, वह समझौते करने के लिए आसानी से तैयार हो जाती हैं और कोई फैसला लेते समय सभी लोगों की राय को महत्व देती हैं। जो कि कार्यस्थल पर विभिन्न लोगों के समूह को एक लक्ष्य के प्रति एक साथ लेकर चलने में महत्वपूर्ण गुण हैं।

लोगों को सशक्त करना बेहतर- मातृत्व का नैसर्गिक गुण एक ऐसी विशेषता है जो हर महिला को ज्यादा व्यावहारिक बनाता है। सफलता के बावजूद उनके पैर जमीन से अधिक मजबूती से जुड़े होते हैं। साथ ही वह अपने साथ के उम्मीदवारों को भी सशक्त बनाने में यकीन रखती हैं।

पूर्वाभासी

चूंकि महिलाओं का दायां भाग अधिक सक्रिय रहता है, इसके कारण वह पूर्वाभासी होती हैं यानी समस्याओं की आशंका या भावी परेशानियां क्या हो सकती हैं, उसका अनुमान वह जल्दी लगा लेती हैं। पुरुषों की तुलना में वह समस्या को जल्दी पहचानकर अनियंत्रित होने से पहले उसमें सुधार कर लेती हैं। संकट के समय में उनके विचार कोश से निकलने वाले विचार दूसरों की तुलना में अलग होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की धनी होने के कारण वे आपात स्थितियों के प्रबंधन में अधिक माहिर होती हैं।

काम की स्पष्टता

वह काम और उससे अपेक्षा को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकती हैं। साथ ही फीडबैक देने में भी उनके कौशल का कोई सानी नहीं है। वह प्रशंसा करने में पुरुषों की तुलना में अधिक उदार होती हैं और अहम या अहंकार से परे वह दूसरों की राय को भी अधिक सहजता से स्वीकार करती हैं। कम्यूनिकेशन स्किल और आपसी संबंधों को बनाने का कौशल उनमें कहीं अधिक बेहतर होता है।

अनुकूलता

प्रकृति से महिलाएं बदलती परिस्थितियों को अधिक सहजता व अनुकूलता से स्वीकार कर लेती हैं।

कार्य निर्धारण में बेहतर- महिलाओं को अधिक व्यवस्थित माना जाता है। इसलिए पुरुषों की तुलना में काम को बेहतर तरीके से वर्गीकृत कर सौंपने का काम उन्हें बखूबी आता है।

यह बिंदु हमें बताते हैं कि कार्यस्थल पर किन क्षेत्रों में महिलाएं बेहतर स्थिति में हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि प्राकृतिक गुणों के तौर पर बेहतर प्रबंधन की योग्यता होने के बावजूद पावरफुल पदों पर उनकी उपस्थिति बड़ी संख्या में देखने को नहीं मिलती। हालांकि किसी भी एक व्यक्ति में फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष, प्रबंधन के सभी गुणों का होना संभव नहीं है। पर महिलाओं को उनके प्राकृतिक गुणों के मद्देनजर अधिक बेहतर तरीके से अच्छे प्रबंधन के क्षेत्र में ढाला जा सकता है।

कार्यस्थल भी, घर भी

घर-परिवार और ऑफिस की दोहरी भूमिकाओं में कई बार महिला उम्मीदवारों के समक्ष नौकरी छोड़ने, पदोन्नति से पीछे हटने, तनाव ग्रस्त रहने या फिर काम में बदलाव करने की मजबूरियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में क्या कहती है मेरी

सेविंस्की, आइये जानें

अपनी क्षमताओं, लक्ष्यों और पारिवारिक जरूरतों का व्यावहारिक मूल्यांकन करें। तनाव मुक्त रहने के लिए क्षमता अधिक होने के बावजूद निचले स्तर पर ही काम करने की मजबूरियों से बची रहेंगी। आवश्यक काम के घंटों में बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकेंगी।

अपनी क्षमताओं के अनुरूप पद पर काम करते हुए ऐसी जगह नौकरी तलाशें जहां की कार्य संस्कृति में आपको कम से कम समायोजन करना पड़े। देर रात तक काम करना या फिर लंबे या अधिक टूर पर जाना आदि बातों को पहले से जान लें।

परिवार के सदस्यों के समक्ष अपनी काम और घर के संबंध में सोच और इच्छाओं को स्पष्ट कर दें। भविष्य में तनाव के बड़े मुद्दे बनने से रोकने में मदद मिलेगी।

आवश्यकता पड़ने पर यदि संभव है तो अपनी जिम्मेदारियों और तनाव के कारण को परिवार और सुपरवाइजर के साथ शेयर करें।

कार्यस्थल पर प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करें।

यदि आपकी वर्तमान स्थिति सही नहीं है या फिर आपकी क्षमता और स्थिति के अनुरूप नहीं है तो उसमें बदलाव करने में देरी ना करें।

क्यों नहीं चाहिए महिला उम्मीदवार

महिला उम्मीदवार की क्षमताओं को लेकर भले ही किसी को कोई शक नहीं हो पर अभी भी कंपनियां विभिन्न पदों पर महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं किए जाने के संबंध में विभिन्न तर्क देती हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

ल्शादी के बाद बदल जाती है महिलाओं की प्राथमिकता, काम की जगह परिवार होता है प्रमुख

सभी शिफ्ट में काम करने में सहज नहीं होती।

बिजनेस टूर के दौरान उनकी सुरक्षा और रहने के लिए करनी होती है विशेष देखभाल।

कंपनियों का कहना है कि ग्राउंड लेवल पर बेहतर काम नहीं कर पाती। स्वभाव से नाजुक होने के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोलमाइनिंग जैसे क्षेत्रों में कंफरटेबल नहीं होती।

निफ्ट प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। निफ्ट प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nift.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

NIFT 2024 परीक्षा तिथि

एनटीए की तरफ से बीडीएस और बीएफटेक, एमडीएस, एमएफएम और एमएफटेक और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 05 फरवरी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

NIFT 2024 परीक्षा पैटर्न

जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए निफ्ट 2024 परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी, जबकि क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट पेपर-आधारित परीक्षण मोड में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न पत्र दो भाषाओं में होगा यानी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। उम्मीदवारों को निफ्ट आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के अनुसार उसी माध्यम में उत्तर देना आवश्यक है। अनुवाद के कारण हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी अस्पष्टता के मामले में, बाद वाले को अंतिम माना जाएगा।

NIFT Admit Card 2024 ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nift.ac.in पर जाएं। निफ्ट एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। निफ्ट प्रवेश परीक्षा पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। लॉगइन करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब इसे डाउनलोड करें।

आईसीएआई सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल मई परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल मई परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज, 2 फरवरी से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org के माध्यम से आईसीएआई सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

आवेदन की समयसीमा- आईसीएआई सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल परीक्षा 2024 के लिए आवेदन विंडो 2 फरवरी से 23 फरवरी, 2024 तक खुली रहेगी। शेड्यूल के अनुसार, ICAI CA फाउंडेशन परीक्षा 20, 22, 24 और 26 जून को आयोजित की जाएगी। ग्रुप 1 के लिए CA इंटरमीडिएट कोर्स परीक्षा 3, 5 और 7 मई 2024 को आयोजित की जाएगी और ग्रुप 2 के लिए परीक्षा 9, 11 और 13 मई, 2024 को आयोजित की जाएगी।। समूह 1 के लिए अंतिम पाठ्यक्रम परीक्षा 2, 4 और 6 मई, 2024 को और समूह 2 के लिए 8, 10 और 12 मई, 2024 को निर्धारित है।

परीक्षा	तारीख
सीए फाइनल परीक्षा की तारीखें	समूह 1 - 2, 4, 6 मई
	समूह 2 - 8, 10, 12 मई
सीए इंटर परीक्षा तिथि	समूह 1 - 3, 5, 7 मई
	समूह 2 - 9, 11, 13 मई
अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षण (आईएनटीटी - एटी)	10 और 12 मई
सीए फाउंडेशन परीक्षा तिथि	20, 22, 24, 26 जून

इसके अलावा, परीक्षा शहर, परीक्षा के माध्यम में बदलाव चाहने वाले छात्रों के लिए, सुधार विंडो 3 से 9 मार्च, 2024 तक खुली रहेगी।

हर किसी को घूमना बहुत अच्छा लगता है। अपने कदमो के नीचे दुनिया को नाप लेने की ख्वाहिश उस वक्त मन में रह जाती है जब लगता है की घूमने से जीवन नहीं चलने वाला है। लेकिन अब समय बदल गया है। लोग घूमते-घूमते पैसा कमा रहें है और इस क्षेत्र में अपना कैरियर भी बना रहे हैं। अगर आप घूमने के शौक़ीन है तो आप इस तरीके से अपने पैशन को प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं।

ट्रेवलिंग के क्षेत्र में बेहतर कैरियर बनाकर आप कमा सकते हैं अच्छा पैसा

बनाये अपनी कंपनी

आप खुद की एक ट्रेवल एजेंसी बना सकते है। इसके जरिये आप लोगो को घुमाने ले जा सकते है और साथ में आप खुद जाए तो आपका भी घूमना हो जाएगा। आज के समय में लोग अलग अलग जगह जाने की चाहत रखते है और इसके लिए वो ट्रेवल कंपनियों से सारे इंतजाम करने को कहते है। आप लोगो के घूमने की व्यवस्था करें जैसे की उनके आने जाने, रुकने, खाने और अच्छी जगह देखने का, और इसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा और खुद आप घूम भी लेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनिया है जो ये काम करती है और वो बेहतर पैसा कमा रही हैं। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं और उसे प्रमोट करके लोगो को बताये की आप घूमने से सम्बंधित सभी जरूरी इंतजाम करते है।

ट्रेवल ब्लॉगर

आज के समय में युवाओ को ब्लोगिंग का चस्का लगा हुआ है। हर कोई अपना ब्लॉग बना रहा है। आप घूमने के साथ साथ अपना ब्लॉग लिखकर पैसा कमा सकते है। आप अपनी एक वेबसाइट या ब्लॉग बनवाएं और उसमे आप अलग अलग जगहों की तस्वीरे और वहां का अनुभव डालें। जो लोग किसी जगह घूमने जाते है उससे पहले वहां की बातें जानना चाहते है और इसकी जानकारी आप अपने ब्लॉग की सहायता से दे सकतें है। हालाँकि इसमें कमाई थोड़ी लेट होती है लेकिन एक समय के बाद इतने पैसे आने लगते है की आप हर जगह आसानी से घूम सकते है। इसके लिए आपको किसी ऑफिस में नहीं बैठना पड़ेगा।

यूट्यूब चैनल

अगर आप घूमने के शौक़ीन है और उसके साथ साथ पैसा कमाना चाहते है तो अप खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते है। इसमें आप जिस जगह घूमने जा रहे हैं वहां की अलग बातें, खान-पान, रहन सहन और बोली भाषा डालें। लोगो को ये देखना बहुत पसंद होता है। इस चैनल के जरिये आप बेहतर पैसा भी कमा सकते हैं और आपके घूमने का शौक भी पूरा होता रहेगा। आप इसके लिए एक कैमरा लीजिए और वहां बेहतर वीडियोस शूट कीजिए और फिर उसे अपने चैनल में डालियें।

टूर गाइड

आप जब घूमने जाते है तो उस जगह आपको कुछ लोग मिलते है जो पूरी जानकारी देते है उन्हें आप टूर गाइड कहते है। आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए अलग अलग Tourism and Hospitality Management Course भी कर सकते है। आप अलग अलग जगहों की जानकारी रखे और जहाँ भी जाएँ वहां लोगो को उस जगह की जानकारी दे और इसके बदले आप उन लोगो से पैसे की डिमांड कर सकते हैं। लोग आपको पैसे भी देंगे और आपका घूमना भी हो जाएगा। यह बहुत बेहतर तरीका है जिससे आप पैसे कमाने के साथ साथ अपने घूमने का शौक पूरा कर सकते है।

कंपनियों के साथ जुड़ें

आज के समय में बहुत सारी ऐसी कम्पनियाँ है जो ऐसे लोग हायर करती हैं जो की घूमने के शौक़ीन हों। इसमें उन्हें अलग लाग जगह जाना होता है और उनकी कंपनी की साईट पर वहां का अनुभव लिखना होता है और बढ़िया बढ़िया पिक्स अपलोड करनी होती है। इसके बदले कम्पनियाँ आपको आने जाने और रहने खाने का खर्च देती है और आपसे बेहतर काम की उम्मीद करती है। मेक माय ट्रिप (MakeMyTrip), गोआईबिबो (Goibibo) जैसी कम्पनियां कुछ ऐसे लोग जरूर अपने पास रखती है। घूमने के साथ साथ काम करने के ये सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ से आप पैसे कमा सकते है और साथ साथ अपने घूमने के शौक को भी पूरा कर सकते है।

वेब पत्रकारिता में कैरियर

भारत में बढ़ते संचार साधनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करियर के अवसर उजले हुए हैं। दिनोदिन समाचार चैनलों, अखबारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पत्रकारित्रा पहले जहां अखबारों, पुस्तकों में हुआ करती थी, वहीं इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन के बीच वेब पत्रकारिता का जन्म हुआ। इंटरनेट बढ़ते समाचार पोर्टलों से वेब पत्रकारिता में योग्य पत्रकारों की मांग बनी रहती है।

क्या होती है वेब पत्रकारिता

जिस प्रकार अखबारों, पत्रिकाओं में खबरों के चयन, संपादन या लेखक होते हैं। यही कार्य इंटरनेट पर किया जाता है। हर व्यक्ति तेजी से खबरें चाहता है। युवाओं की भी पसंद इंटरनेट बनता जा रहा है। पहले जहां इंटरनेट कम्प्यूटर तक सीमित था, वहीं नई तकनीकों से लैस मोबाइलों में भी इंटरनेट का चलन बढ़ता जा रहा। किसी भी जगह कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वेब पत्रकारिता का ही कमाल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में किसी भी देश का अखबार या खबरें पढ़ सकते हैं। यहां कार्य में भी तेजी होनी चाहिए। खबर लिखकर उसका संपादन ही नहीं, बल्कि लगातार उसे अपडेट भी करना पड़ता है। वेब पत्रकारिता में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए खबरों को समझकर उन्हें प्रस्तुत करने की कला, तकनीकी ज्ञान, भाषा पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। न्यूज पोर्टल के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली साइटों की संख्या भारत में कम हैं।

ऐसी साइटों की संख्या ज्यादा है जो अपने वेब के लिए सामग्री अपने चैनलों या अखबारों से लेती हैं। स्वतंत्र न्यूज पोर्टल में वेब पत्रकार बनकर आप करियर बना सकते हैं। खेल, साहित्य, कला जैसी साइटों पर करियर की उज्जवल संभावनाएं रहती हैं। मास कम्यूनिकेशन या जर्नलिज्म में डिप्लोमा या डिग्री लेकर आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

12वें मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन राजभवन में ली पद की शपथ

रांची। झामुमो उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने रांची के राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन को गुरुवार को मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया था, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल से सरकार बनाने के उनके दावे को जल्द से जल्द स्वीकार करने का आग्रह किया था क्योंकि राज्य में भ्रम था, जो बुधवार को हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री के बिना था। कांग्रेस और राजद कोटे से भी एक-एक विधायक मंत्री बने हैं। यह कही ना कही सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कवायद है। कांग्रेस के आलमगीर आलम ने रांची के राजभवन में झारखंड कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राजद के सत्यानंद भोक्ता ने रांची के राजभवन में झारखंड कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन को अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

हेमंत सोरेन को कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नईदिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। उन्हें 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में ईडी पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि अब से कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

मोदी से मिलना कोई गुनाह नहीं, सजा भुगतने को तैयार

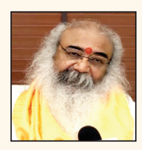

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित भी किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निमंत्रण स्वीकार करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। इसके बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निष्कासित करने का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पूरे मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार पीएम मोदी से मिला। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को चंडीगढ़ में नए मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका को बिना कोई तारीख बताए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा मंगलवार को एक चौथाई चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद। आप और कांग्रेस ने वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और कुमार को दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए अदालत का रुख करने के लिए प्रेरित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। सिंघवी ने एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह गलत तरीके से काम करते दिख रहे हैं। यह गंभीर है। हम तत्काल सूची की मांग कर रहे हैं।

केजरीवाल ने पांचवीं बार दिया ईडी के समन को गच्चा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्टीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश होना था लेकिन लगातार पांचवी बार उन्होंने ईडी के समन को गच्चा देते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनकी गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। मीडिया के अनुसार ऐसा लगातार पांचवी बार हो रहा है, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के बुलावे पर पूछताछ के लिए नहीं जा रहा हैं। मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि ईडी का सीएम केजरीवाल को भेजा जा रहा समन उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास है। मालूम हो कि पिछले चार महीनों में एजेंसी ने चार समन जारी किया था और उसमें पेश न होने के बाद ईडी ने बुधवार को फिर से एक नया और पांचवां समन जारी किया। जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अवैध बताया गया है।

पीएम मोदी ओडिशा-असम में आज देंगे 79000 करोड़ का तोहफा

कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार और रविवार को ओडिशा और असम का दौरा करेंगे और इस दौरान करोड़ों रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उसके मुताबिक, प्रधानमंत्री तीन फरवरी को दोपहर दो बज कर लगभग 15 मिनट पर ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री असम की यात्रा करेंगे जहां वह चार फरवरी को 11 बज कर लगभग 30 मिनट पर गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

पीएमओ ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ओडिशा के संबलपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण किया जाएगा और कुछ की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के धामरा-अंगुल पाइपलाइन खंड (412 किलोमीटर) का उद्घाटन करेंगे। 'प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा' के तहत 2,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी।

प्रधानमंत्री मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा पाइपलाइन के %नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड% (692 किलोमीटर) की आधारशिला भी रखेंगे। 2,660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाली यह परियोजना ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में सुधार करेगी।

संबलपुर में इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 28,980 करोड़ रुपये की कई बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इनमें से कुछ को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जिन परियोजनाओं को वह राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एनटीपीसी दार्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2×800 मेगावाट) और एनएसपीसीएल राउरकेला पीपी -2 विस्तार परियोजना (1×250 मेगावाट) शामिल हैं। वह ओडिशा के अंगुल जिले में एनटीपीसी तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चरण तीन (2×660 मेगावाट) की आधारशिला भी रखेंगे।

ये बिजली परियोजनाएं ओडिशा के साथ-साथ कई अन्य राज्यों को कम लागत वाली बिजली की आपूर्ति करेंगी। प्रधानमंत्री 27,000 करोड़ रुपये से अधिक की नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसी) तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए यह अत्याधुनिक परियोजना विश्वसनीय, सस्ती और चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करेगी, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी और देश की आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रधानमंत्री अंगुल जिले के तालचेर कोलफील्ड्स में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं और लाजकुरा रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस) में भुवनेश्वरी चरण-1 सहित महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लगभग 2,145 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ये परियोजनाएं ओडिशा से शुष्क ईंधन की गुणवत्ता और आपूर्ति को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित ईब वैली वाशरी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्गों की तीन सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिन्हें लगभग 2110 करोड़ रुपये की संचयी लागत से विकसित किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री लगभग 2,146 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री पुरी-सोनपुर-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो इस क्षेत्र में रेल यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।

प्रधानमंत्री आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वह झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन का लोकार्पण करेंगे। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर जाने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है।

इस प्रयास में एक और कदम के रूप में प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना (मां कामाख्या पहुंच गलियारा) शामिल है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना के तहत मंजूरी दी गई है। यह गलियारा कामाख्या मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री 3400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसके तहत 38 पुलों सहित 43 सड़कों को दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री दोलाबाड़ी से जमुगुड़ी और विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर तक चार लेन की दो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

ये परियोजनाएं ईटानगर से संपर्क को बेहतर बनाने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। क्षेत्र की जबरदस्त खेल क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

इन परियोजनाओं में चंद्रपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाना और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना शामिल है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा, करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए आधारशिला भी उनके द्वारा रखी जाएगी।

डीके सुरेश को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा

राहुल-सोनिया सहित इंडिया गठबंधन के नेता चुप क्यों?

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक कांग्रेस नेता के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राज्यसभा के बाहर की गई टिप्पणी पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी सांसद के बयान पर सदन में चर्चा नियमों का उल्लंघन नहीं है। चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस सांसद के बयान को अपमानजनक और भड़काऊ बताते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस की विचारधारा को विभाजनकारी करार दिया।

दरअसल, पूरा विवाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई के बयान से जुड़ा है। राजधानी की बंगलूरू ग्रामीण लोकसभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश होने के बाद कहा, दक्षिण भारत के साथ नाइंसाफी होती है। उन्होंने कथित राजकोषीय अन्याय का जिक्र करते हुए एक अलग दक्षिण राष्ट्र बनाने का आह्वान भी कर डाला। इस विवादित बयान के बाद गोयल ने राज्यसभा में कहा कि देश को बांटने की सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एकजुट राष्ट्र ऐसे किसी भी आह्वान को बर्दाश्त नहीं करेगा।

कांग्रेस सांसद की टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग पर गोयल के बाद खरगे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हम देश को तोड़ने वाले किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह बयान किसी भी पार्टी का हो...चाहे वह मेरी पार्टी का हो या उनकी (भाजपा) पार्टी का, या किसी और का। कोई कहे या न कहे, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे यही कहूंगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है और एक रहेगा। खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि देश को एकजुट रखने के मकसद के लिए ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

खरगे ने सवाल किया, क्या ऐसी पार्टी देश को तोड़ने की बात कर सकती है? उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेगी। जो बात डीके सुरेश ने कही भी नहीं, उन्हें सदन में दोहराना ठीक नहीं है। इससे पहले गोयल ने शुक्रवार सुबह 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर डीके सुरेश के बयान से जुड़ा मुद्दा उठाया। गोयल ने कहा कि डीके सुरेश का ताजा बयान पार्टी की विभाजनकारी सोच का उदाहरण है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए भी भारत के संविधान की शपथ जरूरी है। उन्होंने कहा, निर्वाचित होने के बाद सांसदों को संविधान के प्रति निष्ठा और देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने की शपथ लेनी होती है। उन्होंने सुरेश का नाम लिए बिना कहा कि इस बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भारत के संविधान पर हमला होने के साथ-साथ देश की संप्रभुता और अखंडता का अपमान है।

उन्होंने कहा, यह बयान उस दिन दिया गया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर रही थीं। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप पेश करता है। जबकि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई का बयान कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। गोयल का आरोप है कि कांग्रेस ने अतीत में भी देश को बांटा है।

खेल
प्रमुख समाचार

पहले दिन का खेल खत्म, भारत के स्टंप तक छह विकेट पर 336 रन

नईदिल्ली। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के नाबाद 179 रन की मदद से भारत ने शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन स्टंप तक 6 विकेट गंवाकर 336 रन बना लिये। हैदराबाद में 80 रन की पारी खेलने वाले जायसवाल ने अपनी नाबाद पारी में अभी तक 17 चौके और छह छक्के लगाएं हैं। वहीं इस युवा बल्लेबाज ने श्रेयस अय्यर (27) के साथ 90 रन की भागीदारी निभायी। स्टंप तक आर अश्विन पांच रन बनाकर जायसवाल का साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर और रेहान अहमद ने दो दो विकेट लिये।

विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में शुक्रवार को भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम इंडिया को रोहित शर्मा (14) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। जब लगा कि गिल की आंखें जम गई हैं वह 34 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार बन गए। आने वाले ओवरों में श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर जायसवाल ने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और टीम के स्कोर को 150 के पार ले गए। लेकिन इसी बीच अय्यर (27) को टॉम हार्टली ने आउट कर दिया। अब स्कोर 179-3 हो चुका था। ऐसे में जायसवाल ने नए पार्टनर रजट पाटीदार, जो इस मैच के साथ अपना डेब्यू भी कर रहे हैं, के साथ पारी को आगे बढ़ाया और शतक जमाया। पाटीदार 32 रन बनाकर आउट हुए। गौर करने वाली बात है कि जायसवाल का यह भारतीय सरजमीं पर यह पहला टेस्ट शतक है। साथ ही मौजूदा भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया पहला शतक भी है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 440 अंक चढ़ा निफ्टी 21,850 के ऊपर

नईदिल्ली। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स ने 1,400 अंक से ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली थी मगर कारोबार के अंत तक सेंसेक्स ने लगभग आधा लाभ खो दिया और 440 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ने भी 156 अंक की बढ़त दर्ज की। 21,854 अंक पर बंद होने से पहले यह 22,127 अंक की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 440.33 अंक यानी 0.61 फीसदी की बढ़त के साथ 72,085.63 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 71,948.77 और 73,089.40 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 156.35 अंक यानी 0.72 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,853.80 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 21,805.55 और 22,126.80 के रेंज में कारोबार हुआ।

आईफोन की बिक्री से एप्पल ने दर्ज किया रिकॉर्ड रेवेन्यू

नईदिल्ली। आईफोन की मजबूत बिक्री से टेक दिग्गज एप्पल का रेवेन्यू अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में डबल डिजिट में बढ़ा। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा कि रेवेन्यू के मामले में भारत में ग्रोथ हुई। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की और रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया। एप्पल का तिमाही रेवेन्यू सालाना आधार पर दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 119.6 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में आईफोन से कंपनी का रेवेन्यू करीब छह प्रतिशत बढ़कर 69.7 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 65.77 अरब डॉलर था। सीईओ कुक ने कहा कि कंपनी ने मलेशिया, मैक्सिको, फिलीपीन, पोलैंड और तुर्किये, इंडोनेशिया, सऊदी अरब आदि सहित अन्य उभरते बाजारों में ऑलटाइम हाई रेवेन्यू दर्ज किया।

राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ अगले हफ्ते खुलेगा

नईदिल्ली। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के वितरण कारोबार से जुड़ी कंपनी राशि पेरिफेरल्स अगले हफ्ते अपना आईपीओ पेश करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अपने 600 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 295-311 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी के बयान के अनुसार, आईपीओ 7-9 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। वहीं, एंकर निवेशकों 6 फरवरी को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। यह आईपीओ पूरी तरह से नए शेयरों पेशकश पर आधारित है और इसमें कोई बिक्री प्रस्ताव शामिल नहीं है। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ से जुटाई गई राशी का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इश्यू में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 15% हिस्सा हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए और 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है।

टाटा मोटर्स ने 7,025 करोड़ रु. का नेट मुनाफा दर्ज किया

नईदिल्ली। टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 24 की दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसका नेट मुनाफा बढ़कर 7,025 करोड़ रुपये हो गया है। एलएसईजी डाटा के मुताबिक, यह अनुमान था कि कंपनी 4,451 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा दर्ज करेगी। भारत की सबसे वैल्यूएबल कारमेकर कंपनी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हुए 7,025 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा दर्ज किया। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 2,958 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा दर्ज किया था। अगर सालाना आधार पर देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए दोगुना से ज्यादा का नेट मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी के प्रॉफिट की मुख्य वजह लग्जरी कार यूनिट जैगुआर लैंड रोवर की दमदार बिक्री बताई जा रही है।

अंतरिम बजट में किसी के लिए कुछ खास नहीं

अनिल तिवारी

आम जनता को उम्मीद थी कि चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार राहत उपायों के साथ-साथ नौकरी पेशा मध्य वर्ग को भी लुभाने का प्रयास करेगी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं कर सरकार ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है।

हालांकि केंद्र की सत्ता पर अपनी तीसरी पारी को लेकर आश्वस्त मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में गरीब, महिला, अति पिछड़ावर्ग, अन्नदाता किसान को आगे कर अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर, 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देने का दावा किया है।

वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में आयकरदाताओं को थोड़ी सहूलियत मिली थी। चुनावी साल होने के कारण इस बार भी लोगों को राहत की उम्मीद थी। वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट में छूट न देने की परंपरा को रेखांकित करते हुए बदलाव नहीं करने की बात तो कही लेकिन लगे हाथों कॉरपोरेट टैक्स को 30त्न से घटाकर 22त्न कर दिया। मार्च 2025 तक सोवरेन फंड्स पर टैक्स छूट बढ़ा दी है, साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है।

चूंकि यह बजट आसन्न लोकसभा चुनाव की चुनौतियों के ठीक पहले पेश किया गया है इसलिए इसका फोकस और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखता है और इसमें भ्रम की कोई स्थिति नहीं दिखती। अपनी अगली पारी को लेकर पूरी तरह से तैयार मोदी सरकार ने 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के रोडमैप को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, और बजट के अधिकतर प्रावधान इसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास जैसे हैं। चाहे बजट का आकार हो या प्रावधानों के प्रकार दोनों का फोकस इसी बात पर है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार कैसे दी जाए? और शासन सत्ता में बने रहने के लिए समाज के बड़े समूह को कैसे साध कर रखा जाए?

चुनावी लिहाज के हिसाब से महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब तबके की बड़ी आबादी को जोड़े रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस क्रम में अगले 5 साल में 2 करोड़ नए मकानों का निर्माण, छत पर सौर प्रणाली लगाने से सीधे एक करोड़ परिवारों को जोड़ने का वादा, ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शीघ्र समिति का गठन, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए टीकाकरण पर जोर, आयुष्मान भारत योजना से आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को जोड़ने, पशुओं को बीमारी से बचाने, मत्स्य उत्पादन के निर्यात बढ़ाने, 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने को प्राथमिकता दी गई है।

इसके साथ ही अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने का दावा किया है। साल 23-24 का रक्षा बजट 6.02 लाख करोड रुपए था जो वर्ष 22- 23 की तुलना में 13त्न अधिक था, इस बार यह बढ़कर 6.2 लाख करोड़ हो गया है, यानी रक्षा के क्षेत्र में 3.4त्न की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भी वृद्धि करते हुए 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह वित्त वर्ष 2023 में रेलवे बजट 2.4 लाख करोड रुपए का था इस बार इसे बढ़ाकर 2.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अंतरिम बजट में तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर की घोषणा हुई है तथा यह भी कहा गया है कि 40000 रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन में बदला जाएगा। बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से जून 1997 में एक अलग विभाग के रूप में गठित उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को अंतरिम बजट में 2.3 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय के बजट में भी वृद्धि करते हुए पूर्व के 1.96 लाख करोड रुपए की जगह अबकी बार 2.03 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी 1.57 लाख करोड रुपए की जगह अंतरिम बजट में 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

प्रशासन को नोटिस जारी; मांगा जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में आठ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका देकर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है । जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने मामले में शासन से जवाब मांगा है साथ ही वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। याचिका के अनुसार कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में वन विभाग में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत सीजीपीएससी द्वारा साल 2021 में वन सेवा भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 3 जून 2023 को इस परीक्षा का रिजल्ट सीजीपीएससी द्वारा जारी कर मुख्य एवं अनुपूरक सूची जारी की गई। इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षण रायपुर कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण के बाद 12 सितंबर 2023 को शारीरिक मापदंड परीक्षण लिया गया। इसके बाद से गड़बड़ी शुरू हो गई। इस गड़बड़ी के खिलाफ बस्तर के योगेश

बघेल, मधुसूदन मौर्य व अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि 12 सितंबर को आयोजित शारीरिक मापदंड परीक्षण में 4 घंटे के भीतर 26 किलोमीटर पैदल चलना था, जिसमें 20 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षण में असफल रहे। लिहाजा वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों के स्थान पर फिजिकल टेस्ट के लिए मौका दिया जाना था। अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लिए जाने पर अनुपूरक सूची में दर्ज अभ्यर्थियों को मौका नहीं देकर फिजिकल टेस्ट में फेल हुए अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिए जाने का फैसला लिया जाना कहा गया।

छत्तीसगढ़ में स्टार्ट अप शुरू करना हुआ आसान- विकसित भारत की दिशा में सरकार की पहल

रायपुर में खुला इज ऑफ डूइंग बिजनेस का कक्ष

रायपुर. भारत सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है. बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीडीपी की नई परिभाषा गवर्नेंस, डेव्लपमेंट, परफॉर्मेंस बताई है. इसी दिशा में पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी रायपुर में उद्यमियों व करदाताओं की सहूलियत के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस का कक्ष खोला गया है. इससे छत्तीसगढ़ में अब स्टार्ट अप शुरू करना और आसान हो जाएगा.

राज्य के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार कार्य कर रही है. इसे देखते हुए रायपुर में उद्यमियों, व्यवसायियों और करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष बनाया गया है. उन्होंने बताया कि व्यवसायियों व करदाताओं की सुविधा के लिए कार्यालय में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा.

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में भी स्टार्टअप के साथ साथ उद्यमियों को सहूलियत व अधिकतम लाभ मिल सके इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं. चौधरी ने बताया कि प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस का कक्ष खुलने से युवाओं को नए उद्यम शुरू करने में आसानी होगी. इसके साथ ही करदाताओं को सम्पूर्ण जानकारी व सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगी. इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष में मुख्य रूप से व्यवसायियों, करदाताओं, व्यवसायिक संगठनों की सुविधा के लिए प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशालाएं आयोजित होगी. नया उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने, करो के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर एवं विभिन्न अनुमतियां आदि से संबंधित कार्य भी होंगे.

देशभर में दूसरे स्थान पर

नमो एप से मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंच रहे नितेश

रायपुर. नमो एप के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ के युवा कर रहे. इस काम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता एवं गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के पूर्व छात्र परिषद अध्यक्ष नितेश साहू ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है.

बता दें कि नितेश साहू नमो एप के विकसित भारत एम्बेसडर के टास्क के अंतर्गत अब तक 55000 लोगों को नमो एप में जोड़ चुके हैं. नितेश ने 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच सर्वाधिक लोगों को जोड़ा है, जिसके लिए उन्हें विकसित भारत का एंबेसडर बनाया गया है. नमो एप एवं नरेंद्र मोदी इनके आफिसियल साइट से इनके प्रयासों की सराहना कर चुके हैं. साथ ही भाजपा छत्तीसगढ़ के आफिसियल पेज से भी इनके कार्यों को पोस्ट किया गया है.

नितेश ने बताया कि उन्होंने बिलासपुर संभाग के 300 युवाओं को प्रशिक्षित किया, जो नरेंद्र मोदी एप के प्रचार-प्रसार करके प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे. साथ ही नमो एप में जन मन सर्वे, परीक्षा पे चर्चा, मन की बात जैसे इत्यादि कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करा रहे हैं. नमो एप के प्रमोशन के लिए कई प्रकार के नवाचार कर रहे हैं, जिससे युवा काफी आकर्षित हो रहे हैं.

नितेश साहू प्रमुख रूप से चाय पे चर्चा, मेला ङ्क बाजार में निशुल्क टी स्टाल, प्रथम बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं को आकर्षित एवं एकत्रित करने के लिए मैजिक शो, सिंगिंग कांपिटिशन और चित्रकला के कलाकार से नरेंद्र मोदी जी के स्कैच बनाकर लोगों को नरेंद्र मोदी से जोड़ रहे हैं. साथ ही नितेश साहू कॉलेज और कोचिंग स्थान पर जा रहे हैं और नमो एप स्टाल करा रहे हैं.

राहुल की यात्रा के मद्देनजर प्रदेश दौरे पर पहुंचे प्रभारी सचिन पायलट

रायपुर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नए

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 फरवरी यानी आज से तीन दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं।

इस दौरान वे संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर रायगढ़ जिले में बैठक लेंगे।

बता दें कि रायगढ़, सक्ति और कोरबा में आज कांग्रेसजनों के साथ बैठक है। रायगढ़ में तमाम बड़े नेता, पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं इस बैठक में सचिन पायलट, दीपक बैज,

तीन दिन तक रहेंगे

भूपेश बघेल, शिव डहरिया, सप्तगिरी उल्का जैसे तमाम नेता शामिल होंगे।

बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यह बैठक होनी है। वहीं प्रभारी सचिन पायलट कल अंबिकापुर जाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी का समीक्षा बैठक लेंगे। फिर 4 फरवरी को रायपुर आकर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगाःलक्ष्मी राजवाड़े

भ्रष्टाचार के कारण पड़ा पूर्व मंत्री के घर छापा

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में आने ले प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता आएं केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी। उन्होने कहा कि महतारी वंदन योजना को कैबिनेट के बैठक में योजना पर मंजूरी दे दी गई है। सभी महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए मार्च से आने शुरू हो जाएंगे। वहीं पूर्व खाद्य मंत्री के यहां आई टी के छापे में कहा कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार करके बैठी है। वहीं भ्रष्टाचार निकल कर सामने आ रहा है। वहीं वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात के मामले में कहा कि फिलहाल सौजन्य भेंट हुई है आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में काम होगा।

अगले महीने से खाते में आएगी महतारी वंदन योजना की राशि

रायपुर। भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना मार्च से शुरु होगी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी पुष्टि की है। लोरमी में मीडिया से चर्चा में उन्होने कहा कि कैबिनेट में मुहर लगते ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जारी है। अगले महीनें से योजना की शुरुआत हो जाएगी। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी है। विकसित भारत को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'मोदी की गारंटी' के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह यानी कि हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

16 परिवार के 81 लोगों ने की हिंदू धर्म में वापसी

रायपुर। संस्कृति सुरक्षा मंच लगातार गांव गांव में जन जागरण अभियान चला रहा है। इसके चलते अब घर वापसी का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। बीते दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सभा में जहां करीब एक हजार लोगों ने घर वापसी की थी वहीं अब बस्तर में भी बड़ी संख्या में एक साथ घर वापसी का मामला सामने आया है। बस्तर में इतनी बड़ी संख्या में मूल धर्म में वापसी का यह पहला मामला है। जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत कस्तुरपाल में मडियाकरटॉमी समाज के करीब 16 परिवार के 81 सदस्यों ने मूल संस्कृति और सनातन धर्म में वापसी की है। इस दौरान गांव के पुजारी, पटेल, माझी, चालकी, कोटवार, सरपंच सहित गांव के तमाम लोग मौजूद रहे।

धर्मांतरण को रोकने बस्तर में संस्कृति सुरक्षा मंच लगातार गांव गांव में जन जागरण अभियान चला रहा है। विगत दिनों नारायणपुर से दंतेवाड़ा तक यात्रा भी बस्तर संस्कृति सुरक्षा मंच के माध्यम से निकाली गई थी। उसी विषय में बस्तर संस्कृति सुरक्षा मंच के संभाग संयोजक का कहना है कि मिशनरियों के इशारे पर आदिवासियों का धर्मांतरण किया गया था.

और उनके हिंदू न होने का भ्रम भी पैदा किया जा रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए संस्कृति सुरक्षा मंच लगातार गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को जन जागरण कर उन्हें अपने मूल संस्कृति और सनातन धर्म में वापस लौटने की अपील कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मंत्रियों को जिले का प्रभार आबंटित

रायपुर। राज्य शासन द्वारा जिला योजना समिति के अध्यक्षता करने तथा जनसमस्याओं का निराकरण करने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिले का प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से आज जारी आदेशानुसार उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव को बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले का प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल को बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोण्डागांव और नारायणपुर, मंत्री श्री रामविचार नेताम को रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मंत्री श्री दयालदास बघेल को महासमुंद, गरियाबंद और सूरजपुर जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री श्री केदार कश्यप को रायपुर, सुकमा, बीजापुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, मंत्री श्री लखन लाल देवांगन को मुंगेली, कबीरधाम और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदाबाजार-भाटापारा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी को सरगुजा, जांजगीर-चांपा और जशपुर, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज और सक्ती, मंत्री श्री टंकराम वर्मा को धमतरी और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का प्रभार सौंपा गया है।

डीएमएफ की राशि का उपयोग जनहित से जुड़े कार्यों में की जाए

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि डीएमएफ की राशि गाइडलाइन के अनुरूप व्यय की जाए। उन्होंने कहा कि डीएमएफ मद के अंतर्गत जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा सहित आवश्यकतानुसार अधोसंरचना की पूर्ति की जा सकती है। वे आज कोरबा में आयोजित जिला खनिज न्यास संस्थान के शासी परिषद को सम्बोधित कर रहे थे, बैठक में उन्होंने डीएमएफ के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। देवांगन ने कहा कि कोरबा आदिवासी बाहुल जिला है और प्रधानमंत्री ने जिले के खनिजों से प्राप्त रायल्टी से संबंधित जिले के विकास हो सके इसके लिए अनेक अधिकार परिषद को दिए हैं। डीएमएफ से जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा सहित आवश्यकतानुसार अधोसंरचना की पूर्ति की जा सकती है। बैठक में उन्होंने विभागों और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की और कहा कि जिले के विकास से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्र ही प्रस्तुत करें। विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, विधायक रामपुर श्री फूलसिंह राठिया और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर ने भी सम्बोधित किया। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने शासी परिषद अन्तर्गत बैठक के विषय में विस्तार से जानकारी दी।

क्रेडा द्वारा स्वीकृत 115 संयंत्रों के कार्यों को 20 तक पूर्ण करने के निर्देश

रायपुर। क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश सिंह राणा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से क्रेडा द्वारा संचालित बायोगैस परियोजना अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सहयोग से स्थापित व स्थापनाधीन बायोगैस संयंत्रों एवं घरेलू बायोगैस संयंत्रों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 115 संयंत्रों के प्रगतिरत् कार्यों को 20 फरवरी के पूर्व पूर्ण किये जाने और अप्रारंभ कार्यों को इस सप्ताह प्रारंभ कर 25 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रधान कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रदेश के समस्त जिलों के अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। बायोगैस एक स्वच्छ एवं सस्ता ईंधन है जिसमें 55 से 70 प्रतिशत तक ज्वलनशील मीथेन गैस होती है। पशुओं से प्राप्त गोबर को एक विशेष प्रकार के संयंत्र में डालकर इस गैस का निर्माण किया जाता है, गैस निर्माण के पश्चात प्राप्त अपशिष्ट का खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।

भाजपा संगठन में अहम बदलाव, 4 प्रदेश महामंत्री बनाए गए, कार्यकारिणी में कई नये चेहरे

रायपुर. लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्त की है, जिसमें 12 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. इसमें कई नए चेहरे हैं. वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है. इसमें संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, जगदीश रोहरा और भरत लाल वर्मा को प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं. वहीं विकास महतो को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा राजा पाण्डेय को सरगुजा प्रभारी, अनुराग सिंहदेव को बिलासपुर प्रभारी, रजनीश सिंह को बस्तर प्रभारी बनाए गए हैं. वहीं ब्रजेश बिचपुरिया, कृष्णकांत पवार, राशि पवार, प्रभा दुबे, संजू नारायण, गुरु बालदास राजीव पाण्डेय, आरपीएस त्यागी, डॉ. राधेश्याम बारले, एसडी बड़गैयाँ, ओमप्रकाश देवांगन और राहुल टिकरिहा को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाए गए हैं.

नियम-कायदों के उल्लंघन पर 4 खदान सील नियम-कायदों

रायपुर। खनिज एवं राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक साथ कई खदानों पर दबिश दी। टीम द्वारा बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित निम्न श्रेणी चूना पत्थर की कुल 4 खदानों का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा मेसर्स जीएस मिनरल्स, प्रो संजय पवार ग्राम कोसमडीह मस्तूरी, दौलतराम बिधानी ग्राम मस्तूरी, मेसर्स बिलासादाई मिनरल्स, प्रो. संजय छापरिया ग्राम मस्तूरी, मेसर्स कन्हैया मिनरल्स प्रो. प्रकाश चनानी ग्राम मोहतरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम के द्वारा इन चारों खदान मालिकों से पर्यावरण स्वीकृति तथा आवक-जावक से संबंधित पंजी तथा अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। किन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिसके कारण इन चारों खदानों को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। खनिज विभाग द्वारा बिल्हा विकासखण्ड के लच्छनपुर तथा पेण्डरवा स्थित खनिज रेत के 4 स्थलों पर रेत का अवैध भण्डारण मात्रा 150 घन मीटर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। इसी क्रम में राज्य स्तरीय खनिज उड़नदस्ता दलों द्वारा भी बिलासपुर जिले की विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनिजों के अवैध परिवहन करते हुए कुल छह हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जिले की विभिन्न थानों की अभिरक्षा में वाहनों को रखा गया है।

ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर को हटाने की मांग, धरने पर बैठे कर्मचारी और छात्र

रायपुर. ट्रिपल आईटी नया रायपुर के डायरेक्टर डॉ. प्रदीप कुमार सिन्हा को हटाने की मांग को लेकर संस्थान के सभी शैक्षणिक-अशैक्षणिक कर्मचारी और छात्र-छात्रओं ने आज बड़ा प्रदर्शन किया. डायरेक्टर पर कई सारे आरोप भी लगाए और भर्ती प्रक्रिया ड्राफ्ट का दहन भी किया. कर्मचारियों के मुताबिक, कई वर्षो से संस्थान में हो रही भारी आर्थिक अनियमतता, भर्ती घोटला, सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग, संस्थान के एक्ट की अनदेखी, अपने चहेतों को लाभ देने के लिए मनमाने ढंग के नियमो में तोड़मरोड़ और गड़बड़ी करना, केवल अपने चहेतों के वेतन विसंगतियों को दूर करना, कर्मचारियों के प्रमोशन को जानबूझकर विलंबित करना और अपने चहेतों के लिए नियम विरुध्द नए नए नियम बनाकर लाभ देने की कोशिश करना. संस्थान में लगातार योग्य शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा संस्थान छोड़कर जाना या दबाव पूर्वक इस्तीफा दिलवाना कर्मचारियों को जबदस्ती नोटिस देने के लिए उनके रिपोर्टिंग अधिकारियों पर दबाव बनाना, कर्मचारियों को अपने ऑफिस बुलाकर इस्तीफा देने बोलना या देख लेने की धमकी देने जैसे बहुत से विषयों पर संस्थान के कर्मचारियों ने लिखित में सैकड़ों शिकायत संस्थान के बोर्ड से लेकर शासन प्रशासन तक किया, परंतु इस पर कार्यवाही न होता देख कर्मचारियों और संस्थान के विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त है. इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राएं संस्थान को त्रष्ट द्वारा डिफाल्टर घोषित किए जाने सहित डायरेक्टर के अनुचित व्यवहार सहित बहुत से विषय पर नाराज़ चल रहे थे.

हाल ही में जब संस्थान के निदेशक ने जैसे ही कर्मचारियों के लिए नया भर्ती नियम लाया संस्थान के सभी कर्मचारी आंदोलित हो गए और निदेशक के ऑफिस के बाहर विगत 48 घंटों से धरने पर बैठे हैं, परंतु संस्थान प्रबंधन के जिद्द के कारण पहले शैक्षणिक फिर संस्थान के सभी विद्यार्थी भी आंदोलित हो गए और सभी ने एक स्वर में निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार सिन्हा को पदमुक्त करने मांग उठाई है.

लोस निर्वाचन 2024 : 5 से होगी ईव्हीएम मशीनों की जाँच

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन पूर्व सभी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईव्हीएम) की प्रथम स्तर की जाँच (एफएलसी) 5 फरवरी से 14 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जाँच को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिला एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा तकनीकी टीम का ऑनलाइन प्रशिक्षण संपादित कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों में बैलेट युनिट, कंट्रोल युनिट तथा वीवीपेट की प्रथम स्तर की जाँच (एफएलसी) की जाएगी। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने का आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को भी इस संबंध में जानकारी भेजी गई है। श्रीमती कंगाले ने बताया कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के ईव्हीएम को जाँच से पृथक रखा जाएगा जहाँ के निर्वाचन परिणामों को लेकर न्यायालयों में मामले लंबित हैं। शेष सभी क्षेत्रों के ईव्हीएम यूनिटों की 05 से 14 फरवरी तक जाँच पूरी कर ली जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री बी एस पात्रा के पर्यवेक्षण में आयोजित ऑन लाइन प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीनों की जाँच संबंधी सभी आवश्यक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया । साथ ही लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान झारखण्ड की नोडल अधिकारी एवं प्रशिक्षक श्रीमती गीता चौबे ने प्रशासनिक पहलुओं तथा इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक श्री पी सी मंडल ने ईव्हीएम जाँच संबंधी तकनीकी पक्षों पर प्रकाश डाला।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.